• वर्ष-2
• अंक-265
रायपुर, बुधवार 28 जून 2023
• पृष्ठ-6
• मूल्य-3 रु.

samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

सरकारी 15 लाख नौकरी पर कैंची

सात उद्यमों में खत्म हो गए 3.84 लाख रोजगार, 42.5 प्रतिशत कार्यबल नियमित नहीं

जितेंद्र भारद्वाज

केंद्र सरकार में एक तरफ नौकरी लेने वालों की कतार लंबी हो रही है तो दूसरी ओर सरकारी नौकरियों पर लगातार कैंची चलना जारी है। केंद्र में 11 लाख तो सार्वजनिक उद्यमों में 4 लाख पद खाली पड़े हैं। अब यह गारंटी भी नहीं है कि ये सभी पद भरे जाएंगे या नहीं। एआईटीयूसी के राष्ट्रीय सचिव और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी.श्रीकुमार के मुताबिक, वर्तमान सरकार ने आश्वासन दिया था कि देश के बेरोजगार युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

2012-13 से 2021-22 की अवधि के लिए हाल ही में प्रकाशित सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सरकारी निगम और सरकारी सहायक कंपनियां, जो 17.3 लाख लोगों को नौकरियां प्रदान कर रहे थे, मार्च 2022 के दौरान घटकर वह संख्या 14.6 लाख रह गई है।

गत सप्ताह कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्वीट में लिखा था, कांग्रेस सरकारों ने देश में रोजगार देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की उम्दा कंपनियां बनाई थीं। मोदी सरकार में उन कंपनियों की हालत खराब हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के सात उद्यमों में 3.84 लाख रोजगार खत्म हो गए। इन उद्यमों में ठेके व संविदा वाले कर्मचारियों की संख्या 19 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गई है। अच्छी नौकरियां देने वाली इन कंपनियों से

रोजगार खत्म क्यों किया जा रहा है। देश निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग देने वाली इन कंपनियों को मोदी सरकार क्यों बर्बाद कर रही है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में एक ग्राफ भी अटैच किया है। उसमें लिखा है कि बीएसएनएल में 181127, एसएआईएल में 61928, एमटीएनएल में 34997, एसईसीएल में 29140, एफसीआई में 28063, एयर इंडिया में 27985 और ओएनजीसी में 21120 नौकरियों में कमी आई है।

42.5 प्रतिशत कार्यबल नियमित नहीं

एआईटीयूसी के राष्ट्रीय सचिव के मुताबिक, 389 सीपीएसयू में एक सर्वेक्षण किया गया था। इनमें से 284 उद्यम अभी भी चालू हैं। इनकी नौकरियों में 2.7 लाख से अधिक की भारी गिरावट आई है। कुल कार्यबल में से 17 प्रतिशत अनुबंध के आधार पर और 2.5 प्रतिशत स्टाफ, आकस्मिक और दैनिक वेतन के आधार पर काम कर रहा है। 2022 में अनुबंध श्रमिकों की संख्या बढ़कर 36 प्रतिशत हो गई है। वहीं आकस्मिक/दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की संख्या बढ़कर 6.6 प्रतिशत है। इसका मतलब यह हुआ कि 2022 में सीपीएसयू और निगमों में 42.5 प्रतिशत कार्यबल अनुबंध, आकस्मिक या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के तौर पर कार्यरत है।

सर्वेक्षण से पता चलता है कि सात सीपीएसयू में स्थायी कर्मचारियों की संख्या काफी कम हो गई है। प्रमुख सीपीएसयू-बीएसएनएल में कर्मचारियों की संख्या जो 2013 में 2,55,840 थी, घटकर 1,81,127 हो गई है। सेल में 1,86,207 से घटकर 1,24,279 हो गई। मार्च 2022 के दौरान एमटीएनएल में वह संख्या 39,283 से 4,286, एफसीआई में 80,1672 से 52,104 और ओएनजीसी 49,366 से 28,246 हो गई है। भारत जैसे देश में जहां बेरोजगारी चरम पर है, वहां इस तरह से रोजगार घटना, बहुत चिंताजनक है।

श्रीकुमार सवाल उठाते हैं कि निगमों में बंटी 41 आयुध फैक्ट्रियों का भविष्य क्या है। जब 41 आयुध फैक्ट्रियों का निगमीकरण किया गया था तो उस वक्त अक्टूबर 2021 के दौरान 78 हजार कर्मचारी थे। आज वह संख्या 70,000 है। सरकार ने आयुध कारखानों में कोई नई भर्ती नहीं करने का फैसला किया है। आयुध निर्माणियों और सेना कार्यशालाओं में अनुकंपा नियुक्ति को भी एकतरफा तरीके से रोक दिया गया है।

रक्षा मंत्रालय में 2.9 लाख सिविल पद रिक्त

सी. श्रीकुमार बताते हैं कि केंद्र में अकेले रक्षा मंत्रालय के सिविल पदों की बात करें तो 2.9 लाख पद खाली पड़े हैं। वे एआईडीईएफ की ओर से इन पदों को भरने के लिए लड़ रहे हैं। बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में भी नौकरियों की स्थिति ठीक नहीं है। वर्ष 1994 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 41.76 लाख थी, जो आज घटकर 30 लाख रह गई है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में 11 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। रेलवे में 3.5 लाख, रक्षा विभाग में 2.90 लाख और डाक विभाग में 1 लाख पद खाली पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि इन विभागों में काम कम हो गया है, बल्कि पहले के मुकाबले काम कई गुना बढ़ा दिया गया है। आउट सोर्सिंग, ठेका श्रमिकों की तैनाती और आकस्मिक व दैनिक वेतन भोगी श्रमिक आदि के माध्यम से स्टाफ की कमी को पूरा किया जा रहा है।

सरकार खुद श्रम कानूनों का उल्लंघन करती है

श्रम कानूनों के तहत अनुबंध श्रमिकों को केवल मौसमी नौकरियों और सीमित अवधि की नौकरियों के लिए रखा जा सकता है। संविदा और कैजुअल श्रमिकों को स्थायी व बारहमासी नौकरियों पर तैनात नहीं किया जा सकता है। सरकार खुद इसका उल्लंघन करती है। श्रम कानूनों के तहत, नौकरी की कौशल आवश्यकता के आधार पर निर्धारित न्यूनतम वेतन अनुबंध श्रमिकों को अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाना आवश्यक है।

हालांकि ठेकेदार, ऐसे कर्मचारियों के वेतन का 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा ले लेते हैं। ठेकेदार ईपीएफ और ईएसआईसी अंशदान का भुगतान किए बिना आसानी से भाग जाता है। ऐसी स्थिति में अनुबंध कर्मचारी असहाय बने रहते हैं। जब किसी संविदा कर्मचारी की नौकरी करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को बीमा कवरेज सहित कोई लाभ नहीं दिया जाता है।

इन दिनों — राजकुमार सिंह

समान नागरिक संहिता का वादा

22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर धार्मिक संस्थाओं और आम नागरिकों से 13 जुलाई, 2023 तक विचार और सुझाव मांगे हैं। बेशक ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। नवंबर 2016 में भी विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर विचार आमंत्रित किए थे, जिनके आधार पर 2018 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि विभिन्न समुदायों के निजी या पारिवारिक कानून के बदले समान संहिता जरूरी नहीं है। अब फिर उसी तरह सुझाव आमंत्रित करने का अर्थ निकाला जा रहा है कि केंद्र सरकार उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहती है। जब भाजपा शासित गुजरात और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की दिशा में काम शुरू हुआ, तभी से यह कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार दूसरे कार्यकाल के अंतिम चरण में अपना एक और परंपरागत चुनावी वायदा पूरा करने जा रही है। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देनेवाली संविधान की धारा 370 की समाप्ति की तरह देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना जनसंघ काल से ही भाजपा की घोषित वचनबद्धता रही है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पिछली बार से भी अधिक 303 सीटें अकेले दम मिल जाने के बाद भाजपा और मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून से लेकर तीन तलाक और धारा 370 की समाप्ति तक देश पर दूरगामी असर डालनेवाले फैसले लिए। समान नागरिक संहिता ऐसा मुद्दा है, जिसका तार्किक विरोध विपक्ष के लिए आसान नहीं। बेशक मुद्दा नया नहीं है। इतिहास के पन्ने पलटें तो 1835 में अंग्रेजी शासन ने भी महसूस किया था कि भारत को समान नागरिक संहिता की जरूरत है, लेकिन उन्होंने विभिन्न समुदायों के लिए जारी निजी या पारिवारिक कानूनों को छेड़े बिना ही अपराध, सबूत और अनुबंध आदि मामलों में समान कानून की वकालत अपनी रिपोर्ट में की। आजादी के बाद संविधान सभा में भी समान नागरिक संहिता पर विचारोत्तेजक बहस हुई। खासकर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने इसके पक्ष और बी पोकर साहब ने इसके विपक्ष में जो कुछ कहा, वह पढ़ने और विचार करने योग्य है। समान कानून की सोच को अक्सर अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध बताकर उसका विरोध किया जाता है, जबकि सच यह है कि मुस्लिम ही नहीं, बल्कि विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार आदि मामलों के लिए हिंदू समुदाय में भी धार्मिक -परंपरागत कानून हैं। सिख और जैन समुदाय में भी हिंदू लॉ चलता है, जबकि ईसाई और पारसी समुदाय के लिए अलग पर्सनल लॉ हैं। ऐसे में विचार या बहस का मुद्दा संप्रदाय और सत्ता-राजनीति से परे व्यापक राष्ट्रहित होना चाहिए। स्वाभाविक ही अलग-अलग समुदाय के लिए अलग-अलग कानून से जटिलताएं पैदा होती हैं। न्याय प्रक्रिया में भी विलंब होता है। सच यह भी है कि न सिर्फ अमेरिका जैसे देश में, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, सूडान, मलेशिया, मिस्र और इंडोनेशिया सरीखे देशों में भी सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू हैं। ऐसे में समान कानून की सोच सिद्धांतत़ गलत नहीं। हमारा संविधान भी नागरिकों में समानता की बात कहता है।

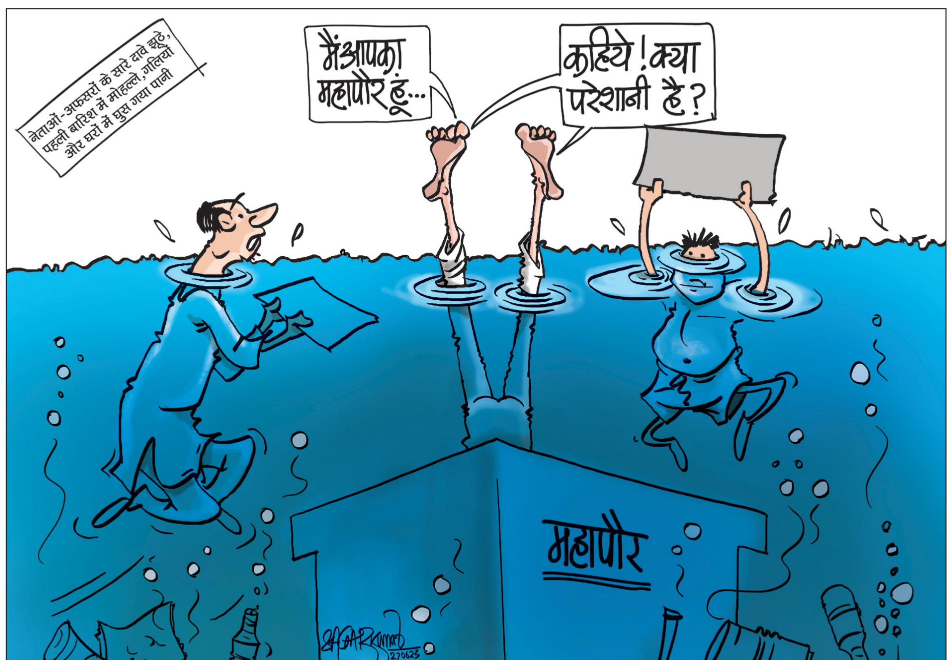

भाजपा का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम शुरू

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लोगों की सेवा करते हुए उनसे मेलजोल बढ़ाने और इसके माध्यम से पार्टी को मजबूती देने का संदेश दिया है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भाजपा के दस लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को जमीनी स्तर पर और मजबूत बनाने के लिए लोगों के दिलों में अपनी अच्छी छवि और जगह बनाने का सिलसिला तेज करना होगा। भाजपा हर चुनाव से पहले इस तरह बूथों को मजबूत करने का कार्यक्रम करती है। माना जा रहा है कि जिस तरह विपक्षी दलों ने एकजुट होकर पीएम मोदी को रोकने की योजना बनाई है, उसे कई राज्यों में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि ऐसे माहौल में %मेरा बूथ सबसे मजबूत% जैसे कार्यक्रमों का महत्व बढ़ गया है।

चुनाव आयोग की सूचना के अनुसार, 2019 के लोकसभा चुनाव में दस लाख से ज्यादा पोलिंग बूथों पर वोट डाले गए थे। भाजपा ने इस चुनाव में कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इसके बाद भी पार्टी ने

यह महसूस किया था कि वह कम से कम 100 लोकसभा क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कमजोर है। उसका मानना था कि चुनावी समीकरणों में उसने जीत अवश्य हासिल कर ली है, लेकिन इन लोकसभा क्षेत्रों में जीत का अंतर काफी कम था, और कड़े मुकाबले में उसे इन सीटों पर हार का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि उसने एक योजना बनाकर इन सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया था।

इसी योजना को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने गत वर्ष अप्रैल में केंद्रीय महासचिव सीटी रवि के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी को देश के 74 हजार बूथों पर पार्टी को मजबूत करने के लिए उपयुक्त योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इनमें अल्पसंख्यक, दलित और जनजातीय मतदाताओं की बहुलता वाले बूथों को प्रमुखता से शामिल किया गया था। समिति ने पाया था कि कम से कम 38 हजार और ऐसे बूथ हैं जहाँ पार्टी को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर हार का स्वाद चखा था, उनमें से भी 100 विशेष सीटों की पहचान की गई है। ये सीटें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों में हैं। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन लोकसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाया जा रहा है। इस प्रकार कम अंतर से 2019 चुनाव में जीती 100 सीटों और हारी हुई 100 लोकसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ संकल्प का मंत्र कार्यकर्ताओं को पढ़ाया जा रहा है जिससे 2024 की लड़ाई में वह मजबूती से उत्तर सके।

प्रमुख समाचार

ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, लगी चोट

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हेलिकॉप्टर को खराब मौसम के कारण मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे उत्तर बंगाल में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री की पीठ और घुटने में मामूली चोट आई है और उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल ले जाया जाएगा। भारी बारिश के कारण हेलिकॉप्टर को उत्तरी बंगाल के सालुगाड़ा में सेना के हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक पंचायत बैठक के बाद बागडोगरा से जलपाईगुड़ी के लिए उड़ान भर रही थीं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल और देश भर के अन्य स्थानों पर आगे बढ़ चुका है। धीमी शुरुआत वाले मानसून ने अब तेजी से प्रगति की है और महाराष्ट्र, पूरे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित कई क्षेत्रों को कवर किया है।

देश का सड़क नेटवर्क नौ साल में 59 प्रतिशत बढ़ाः गडकरी

नयी दिल्ली। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि पिछले नौ वर्षों में किए गए मोदी सरकार के विकास कार्यों के तहत भारत का सड़क नेटवर्क 59 प्रतिशत बढ़कर

दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। गडकरी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज के समय में देश का सड़क नेटवर्क करीब 1,45,240 किलोमीटर है जबकि वित्त वर्ष 2013-14 में यह सिर्फ 91,287 किलोमीटर ही था। इस तरह देश के सड़क नेटवर्क में पिछले नौ वर्षों के दौरान 59 प्रतिशत की उच्च वृद्धि हुई है। उन्होंने मोदी सरकार के नौ वर्षों की उपलब्धियों पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज भारत का सड़क नेटवर्क अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस दौरान सड़क निर्माण के क्षेत्र में भारत ने सात विश्व रिकॉर्ड भी कायम किए।

हाईकोर्ट ने आदिपुरुष मामले में निर्माता को लगाई फटकार

इलाहाबाद। हाई कोर्ट ने फिल्म आदिपुरुष के प्रदर्शन और संवादों के खिलाफ दो जनहित याचिकाओं पर आज सुनवाई की। जस्टिस राजेश सिंह चौहान और श्रीप्रकाश सिंह की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की और फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने फिल्ममेकर्स के साथ-साथ कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को भी लताड़ा है और उस पर सवाल उठाए हैं। बेंच ने कहा कि यहां ये मुद्दा है कि जिस तरह से फिल्म बनाई है, कुछ ग्रंथ हैं जो मिसाल हैं, पूजनीय है। रामचरितमानस का पाठ करने के बाद लोग घर से निकले हैं। कुछ चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सवाल किया कि क्या सेंसर बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? ये तो अच्छा है कि ये हमारे धर्म के बारे में है जहां लोगों ने कोई सार्वजनिक व्यवस्था की समस्या नहीं बनाई। यहां तो भगवान हनुमान, भगवान हनुमान, सीता मां को ऐसा दिखाया गया है। ये चीजें तो इसकी शुरुआत में ही रूक जानी चाहिए।

देश में भारी बारिश के आसार कई राज्यों में अलर्ट जारी

नई दिल्ली। भारत के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक मानसून का मौसम जारी रहने

की संभावना है। आईएमडी के एक बयान में कहा गया है कि अगले पांच दिनों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसमें आगे कहा गया है कि बुधवार को गुजरात में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉ. सोमा सेन रॉय ने कहा कि दिल्ली में अधिकतम तापमान में कमी होगी, अगले 5 दिनों तक तापमान 32-34 डिग्री रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। उत्तराखंड में भूस्खलन की भी आशंका है।

राजद्रोह पर कानून बरकरार रखना जरूरीः विधि आयोग

नई दिल्ली। राजद्रोह पर कानून को निरस्त करने की मांग के बीच विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने मंगलवार को कहा कि कश्मीर से लेकर केरल और पंजाब से लेकर उत्तर-पूर्व तक की मौजूदा स्थिति के कारण %देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए इस कानून को बरकरार रखना जरूरी हो गया है। कानून को बरकरार रखने की पैनल की सिफारिश का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे विशेष कानून विभिन्न क्षेत्रों में लागू होते हैं और राजद्रोह के अपराध को कवर नहीं करते हैं और इसलिए, राजद्रोह पर विशिष्ट कानून भी होना चाहिए। राजद्रोह पर कानून के उपयोग पर विचार करते समय पैनल ने पाया कि कश्मीर से केरल और पंजाब से उत्तर-पूर्व तक वर्तमान स्थिति ऐसी है कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए राजद्रोह पर कानून आवश्यक है।

शिमला समझौता से पहले विपक्ष को मिल गया जीत का फॉर्मूला!

विजय विद्रोही

पटना घोषणा के बाद शिमला समझौते की तैयारी है। कहा जा रहा है कि विपक्ष को जीत का फॉर्मूला मिल गया है। भाजपा के खिलाफ करीब 400 सीटों पर विपक्ष का एक ही उम्मीदवार होगा। इसकी घोषणा 12 जुलाई की शिमला बैठक में हो सकती है। कुल मिलाकर राज्यों की तीन श्रेणियां बनाई जा रही हैं। इन सब के बावजूद विपक्ष में राहुल गांधी को छोड़कर कोई भी अन्य नेता आत्मविश्वास के साथ कहने की हालत में नहीं है कि 2024 में विपक्ष सत्ता में आ जाएगा। तीन सवाल हैं। एक, भाजपा के खिलाफ चार सौ सीटों पर एक ही उम्मीदवार रहा, तो क्या मोदी की हार संभव है? दो, गठबंधन कागजों पर है या जमीन पर भी उतरा है? तीन, सबसे बड़ी पार्टी अगर भाजपा रही, तो विपक्ष कैसे सरकार बना पाएगा?

पहले बात करते हैं, वन टू वन की। पिछले लोकसभा चुनावों के आंकड़ों के संदर्भ में बात की जाए, तो विपक्ष की रणनीति बहुत प्रभावी तो लगती है, लेकिन निर्णायक नहीं। भाजपा ने 46 सीटों पर चार लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से विजय हासिल की थी। उधर विपक्ष ने 23 सीटों पर चार लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। इनमें से कुछ पर विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ जीते थे, तो कुछ में कांग्रेस के खिलाफ, तो कुछ में विपक्ष बनाम विपक्ष के बीच मुकाबला रहा था। जाहिर है कि कुल मिलाकर ऐसी 69 सीटों का गणित बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। भाजपा ने 105 सीटों पर तीन लाख के ज्यादा अंतर से जीत हासिल की

थी। इनमें से आधे में उसका मुकाबला कांग्रेस से हुआ था। ऐसी सीटों की कुल संख्या 131 रही थी। भाजपा को 2014 में 31 फीसदी और 2019 में 37 फीसदी वोट मिले थे और 2024 में 39 फीसदी वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है, तो संयुक्त विपक्ष इन सीटों में सेंधमारी तो जरूर कर सकता है, लेकिन तीन लाख वोटों की दीवार गिरा नहीं सकता।

विपक्ष की नजर ऐसे में उन सीटों पर होनी चाहिए, जहां भाजपा ने दो लाख के अंतर से सीटें जीती थीं। 2019 में ऐसी सीटों की संख्या कुल मिलाकर 236 थी और इसमें से भाजपा ने 164 सीटें जीती थी। यहां भी दिलचस्प आंकड़ा है कि इनमें से भाजपा ने 55 सीटें कांग्रेस के खिलाफ जीती थीं। तो कहानी आकर अटकती है, ऐसी सीटों पर जो भाजपा ने पिछली बार एक लाख के कम के अंतर से जीती थीं। ऐसी सीटों की संख्या कुल 77 थी। अगर विपक्ष पूरा जोर लगा दे, तो यहां भाजपा को तगड़ी पटखनी दी जा सकती है। अगर विपक्ष इन 77 में से 60 सीटें निकाल लेता है, तो भाजपा 302 से घटकर 242 पर आ जाती है। ये आंकड़े यह भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का एक होना कितना जरूरी है। भाजपा ने पिछली बार यूपी में 20 सीटें एक लाख के कम के अंतर से जीती थी। यानी अगर अखिलेश, कांग्रेस, जयंत चौधरी एक हो जाते हैं, तो यूपी में भाजपा की 20 सीटें कम हो जाने की गुंजाइश निकलती है। आंकड़ों के हिसाब से यह आंकड़ेबाजी रोचक लग रही है। लेकिन भाजपा दो बार से चुने जा रहे सांसदों का नया सिरे से सर्वे करवा रही है। एंटी इनकम्बेंसी दूर करने की कोशिश कर रही है।

दूसरा सवाल गठबंधन का है। विपक्ष का कहना है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और झारखंड में मजबूत गठबंधन बन चुका है। इन राज्यों की कुल 142 सीटें (पुडुचेरी मिलाकर) हैं, जहां विपक्ष का स्ट्राइक रेट 80 फीसदी पार होना चाहिए, अगर उसे सत्ता में आते हुए दिखना है। उधर कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां उसे किसी अन्य विपक्षी दल का डर नहीं है। (कुछ हद तक गुजरात में आप का डर जरूर है)। इन राज्यों में कुल 130 सीटें आती हैं, जहां भाजपा पिछली बार 122 सीटें जीती थी। यहां कांग्रेस को अकेले ही लड़ना है।

तीसरी श्रेणी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों की है, जहां कुल सीटें 142 हैं। सारा पेच यहीं आकर फंसा हुआ है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के पाले में गेंद है। दरअसल सारी कुर्बानी यहीं दिखाई जानी है और एकता नहीं हुई तो सारा रायता भी यहीं फैलना है। मजाज साहब यों ही नहीं लिख गए ़ बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना/तेरी जुल्फों का पेच-ओ-खम नहीं है।

शिक्षा से ही व्यक्ति का विकास सम्भवः डॉ. लक्ष्मी ध्रुव

■ **शासकीय श्रृंगी ऋषि एक्सीलेंस इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश उत्सव मनाया गया**

नगरी। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना अंतर्गत संचालित शासकीय श्रृंगी ऋषि उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नगरी में 26 जून को शाला प्रवेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया।सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती तथा छत्तीसगढ़ महतारी की छायाचित्र की पूजा अर्चना,वंदना राजगीत अरपा पैरी की धार गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया ततपश्चात अतिथियों का स्वागत सत्कार स्कूल प्रबंधन की ओर से किया गया।प्रवेश उत्सव में कक्षा एल के जी,पहली,छठवीं,नवमीं में नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया तथा उन्हें चॉकलेट ,पेंसिल ,पुस्तक प्रदान किया गया एवम सरस्वती सायकिल योजनांतर्गत कक्षा नवमी के 37 बालिकाओं को विधायक द्वारा नि:शुल्क सायकिल वितरित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शाला प्रवेश उत्सव के संदेश का वाचन विधायक महोदया द्वारा किया गया।

मुख्य अतिथि विधायक डॉ लक्ष्मी ध्रुव ने विद्यार्थियों ,पालकों को संबोधित करते हुए कहा है कि शिक्षा से ज्ञान मिलती है और ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कभी मरता नहीं है और ना ही कोई चोरी कर सकता है , ज्ञान से ही व्यक्ति जीवन में सब कुछ अर्जित कर सकता है अत: शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति सम्पूर्ण विकास कर सकता है। इस अवसर पर भानेन्द्र ठाकुर अध्यक्ष शाला प्रबंधन एवं विकास समिति, रूद्र प्रताप नाग विधायक प्रतिनिधि, भूषण साहू अध्यक्ष

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नगरी, श्रीमती ललिता साहू पार्षद , दुर्गेश नंदिनी साहू जनपद सदस्य, टिकेश्वर ध्रुव पार्षद, प्रकाश पुजारी पार्षद, जियाउद्दीन रिजवी पार्षद, प्राचार्य एसके प्रजापति ,डीसी खत्री ,आर एल सोनी ,ए एल साव, डोमार सिंह ध्रुव,वासुदेव साहू,डी पी ताम्रकार,आर के कुंभकार,आर पी पटेल,आकांक्षा लाल,शैल चक्रधारी, सोनाली सोनी,गिरधारी साहू,मान सिंह साहू,निधि राठौर, नरेश ठाकुर सहित पालकगण शिक्षक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता सुमन गुप्ता ने किया।

नव प्रवेशी छात्र-छात्राओं का तिलक लगा तथा मुंह मीठा कर स्वागत

शासकीय प्राथमिक शाला चुरियारा पारा नगरी में शाला विकास एवं प्रबंध तथा पालक समिति की बैठक में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर नव प्रवेशी छात्र-छात्राओं का तिलक लगाकर तथा मुंह मीठा कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित एल्डरमैन नरेश छेदैहा,पार्षद अश्वनी निषाद ,पालक जयराम निर्मलकर ने नव प्रवेशी छात्र छात्राओं को गणवेश तथा पुस्तक का वितरण किया। शाला प्रवेश उत्सव के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए एल्डरमेन नरेश छेदैहा ने कहा कि प्रवेश उत्सव को जन-जन का अभियान बनाने के लिए व्यक्तिगत रूचि लेते हुए इससे सभी स्तर पर सफल बनाना होगा ताकि शत-प्रतिशत बच्चों को शाला में प्रवेश एवं ठहराव सुनिश्चित कर सकें तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर समग्र शिक्षा की लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। प्रधान पाठक दीप नारायण दुबे ने उपस्थित पालकों से बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने, विद्यालय में समय-समय पर आयोजित होने वाले बैठकों व कार्यक्रमों में उपस्थित होने का आग्रह करते हुए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर शिक्षिका उमेश्वरी भण्डारी, दुर्गा यादव पुनीता नेताम, पुष्पा ध्रुव, धनेश्वरी नेताम, नागेश्वरी मंडावी, बिंदु कुंजाम, योगिता मरकाम, कृष्ण कुमार वैदे,कमलेश कंचन, विश्वासा मरकाम आदि उपस्थित थे।

विधायक ने किया लहसुनवाही जलाशय के बांध एवं नहरों का जीर्णोद्वार का भूमिपूजन

सिहावा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं उपाध्यक्ष मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकारण डॉ लक्ष्मी ध्रुव के मुख्य आतिथ्य में 25 जून को ग्राम लहसुनवाही जलाशय के बांध एवं नहरों का जीर्णोद्वार कार्य का भूमिपूजन किया। लसुनवाही जलाशय के बांध एवं नहरों का जीर्णोद्वार कार्य सी.सी. लाईनिंग एवं पक्के संरचनाओं का निर्माण कार्य हेतु शासन द्वारा स्वीकृत राशि 208.52 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जलाशय की क्षमता 100 हेक्टेयर का है, उक्त जलाशय खराब हो जाने फलस्वरूप मुश्किल से 10 हे. में सिंचाई हो रहा था। जिसकी क्षमता पूर्ण करने के लिए क्षेत्रीय विधायक डॉ.लक्ष्मी ध्रुव द्वारा शासन एवं विभागीय मंत्री को अवगत कराया,उनके अथक प्रयास से लहसुनवाही जलाशय के बांध एवं नहरों का जीर्णोद्वार एवं पक्के संरचनाओं का निर्माण होगा। यह जलाशय बनकर तैयार होने पर इसका पूर्ण क्षमता 100 हेक्टेयर का होगा, जिसमें निर्बाध गति से सिंचाई होगा। ग्रामवासियों द्वारा विधायक को अपनी गांव के समस्या बताये, जो प्राथमिकता के आधार पर पेयजल की समस्या बताये यह गांव में लगभग 400 लोग निवासरत है। जिसमें 01 बोर चालू है,जिससे निस्तार के लिए काफी कठिनाई हो रही है। ग्रामीणों द्वारा उक्त समस्या बताये जाने पर विधायक द्वारा विभागीय अधिकारी से बात कर तत्काल निराकरण करने को कहा। इसी तारतम्य में ग्राम लहसुनवाही के ग्रामवासियों द्वारा एक और मांग रखी गई कि गंगरेल बांध के केनाल के माध्यम से लहसुनवाही जलाशय को जोड़ने से कम से कम पांच ग्रामों को पानी मिलेगा।

सिहावा क्षेत्र में कमल भंजदेव का धुआंधार जनसंपर्क

नगरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण सम्पर्क से समर्थन के तहत नगरी मंडल जनसम्पर्क करने बस्तर महाराजा व भाजपा सिहावा विधानसभा प्रभारी श्री कमल चंद्र भंजदेव पहुँचे। सर्व प्रथम वें सिहावा पहुँचे जहाँ बस स्टैंड में उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके पश्चात उन्होंने रविवार साप्ताहिक बाजार में आम जनों से संवाद किया जिसके बाद वे भीतर्रास स्थित जग्गनाथ मंदिर में पूजन किया। उसके बाद वें डोंगरीपारा व कैंटतरई में जनसम्पर्क करते हुए सिरसिदा पहुँचे। जहाँ ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया तथा उन्होंने सिरसिदा में स्वयंभू शीतला माता का पूजन आरती किए। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक पिंकी शाह, पूर्व विधायक श्रवण मरकाम, जिला महामंत्री प्रकाश बैस, जिला मंत्री प्रेमलता नागवंशी, जिला मंत्री राजेंद्र गोलछा, मंडल अध्यक्ष मोहन नहाटा, मंडल प्रभारी रवि दुबे, मंडल महामंत्री राजेशनाथ गोसाई, कुकरेल मंडल प्रभारी विकल गुप्ता, राकेश चौबे, मनोहर मनिकपुरी, निखिल साहू, सत्यवती नेताम, शैलेंद्र धनुसेवक, प्रवीण गुप्ता, अंचला यदु, तेजस्विनी साहू, रमेश बोरझा, नरसिंह मरकाम, यशवंत साहू, राजा पवार, दिवयेंद्र परिहार, मोहन पुजारी, यश साहू, चोखे पटेल पटेल, लकेश पटेल, सुनील निर्मलकर, राकेश निर्मलकर, भूपेश साहू, चंद्रभान साहू, तेजनाथ साहू, बृजलाल पटेल, सौहद्रा नेताम, मीना तिवारी, बलराम ध्रुव, गुमान ध्रुव, चित्रांश नागवंशी, संजय सारथी, कमल पटेल, छबी साहू, रूपेश साहू, नमन पटेल, रूप सिंह निर्मलकर, उषा जांगडे, भूषण साहू, नंदलाल नागवंशी, पुरन पटेल व ग्रामवासी उपस्थित रहे।

11 वां वेतन समझौता लागू होने से कामगारों व अफसरों के बीच वेतन विवाद का टकराव बढ़ेगा

■ **कोयला कामगारों को एक जुलाई से मिलेगा नया वेतनमान**

कोरबा। कोल इंडिया के कर्मचारियों का 11 वां वेतन समझौता लागू हो चुका है। ई. वन से ई. फाइव ग्रेड तक कोल अफसरों के वेतन से वरिष्ठ कर्मचारियों का वेतन अधिक हो जाएगा। इसी बहाने अब अफसर भी अपना वेतन वृद्धि करा लेना चाहते हैं। इसे लेकर अब अफसरों के दो संगठन कोल माइंस आफिसर्स एसोसिएशन सीएमएआइ व आल इंडिया एसोसिएशन आफ कोल एक्जीक्यूटिव एआइएसीई ने मोर्चा खोल दिया है।

कोयला कामगारों का 11 वां वेतनमान एक जुलाई 2021 से लंबित था। कोल इंडिया पांच प्रतिशत से ज्यादा मिनिमम गारंटी बेनीफिट एमजीबी देने के पक्ष में नहीं थी। श्रमिक संगठन 18 माह तक जिद पर अड़े रहे और अंतत 19 प्रतिशत एमजीबी पर कोयला मंत्रालय को सहमत होना पड़ा। डिपार्टमेंट आफ पब्लिक इंटरप्राइजेज डीपीई के गाइड लाइन भी आड़े आ रहा था, पर कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने किसी तरह इसका रास्ता भी निकाल लिया और अब एक जुलाई 2023 से नया वेतनमान कोयला कामगारों को मिलने जा रहा। इसके साथ ही कोयला अफसरों ने अब नया विवाद खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि कई ऐसे वरिष्ठ कर्मचारी हैं, जिनका वेतन अब अधिकारियों से भी अधिक हो जाएगा। इसकी वजह से कोल अफसरों में असंतोष देखा जा रहा है। उन्हें उम्मीद थी कि से पहले उनका पे.स्केल अपग्रेड कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आल इंडिया एसोसियेशन आफ कोल एक्जीक्यूटिव, एआइएसीईद्ध

के संयोजक पीके सिंह राठौर ने कोल इंडिया के चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा है कि 11 वां वेतन समझौता लागू होने से कामगारों व अफसरों के बीच वेतन विवाद का टकराव और बढ़ जाएगा। उन्होंने मांग की है कि कार्यकारी अधिकारियों को व्यक्तिगत वेतन पैकेज के माध्यम से वेतन संरक्षण की अनुमति दिया जाना चाहिए, ताकि उनका वेतन श्रमिकों के वेतन से कम न हो। राठौर ने कहा कि अगर उनकी मांगें 30 सितंबर तक नहीं मानी गई, तो कार्यकारी अधिकारी को हड़ताल समेत आंदोलन का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

उधर सीएमएआइ ने भी इस मामले को लेकर रविवार को बैठक कर चिंतन मंथन किया। अध्यक्ष डीएन सिंह ने बताया कि सीआइएल चेयरमैन और कोयला सचिव को नोटिस दिया जा रहा है। 15 जुलाई तक कोयला मंत्रालय में लंबित पे.स्केल के अपग्रेडेशन के प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लिया गया, तो सीएमओएआई कानूनी नोटिस देकर चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ करेगा। उन्होंने बताया कि डीपीई की गाइडलाइन को दरकिनार कर एनसीडब्ल्यूए.11 को मंजूरी देने की भर्त्सना की है। कामगारों के नए वेज का विरोध हम नहीं कर रहे, लेकिन कोल इंडिया व कोयला मंत्रालय ने डीपीई के नियम कायदों का उल्लंघन कर निर्णय लिया है।

डौंडीलोहारा क्षेत्र के अनेक गांव में हुई कांग्रेस की बूथ स्तरीय बैठक

बालोद। डौंडीलोहारा विधानसभा समन्वयक चंद्रिका देशमुख की अगुवाई मे ग्राम उरेटा, गुरामी, भेड़ी, पिंगाल में बूथ स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया बैठक में मुख्य रूप से सरकार के योजनाओं को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया गया वर्तमान कांग्रेस सरकार के द्वारा संकल्प पत्र में किए गए वादों जिसमें किसानों के कर्ज माफी ?25 कुंटल धान खरीदी बिजली बिल हाफ बेरोजगारी भत्ता भूमिहीन मजदूरों को पेंशन ,स्व सहायता समूह के बहनों की कर्ज माफी नरवा गरबा घुरवा बाड़ी गौठान समिति के माध्यम से महिलाओं को मिल लाभ अन्य जनहितकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की जानकारी दी गई बैठक मेंब्लॉक कांग्रेशडौंडीलोहारा अध्यक्ष गोपाल प्रजापति पिछड़ा वर्ग ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती सरोज पटेल एवं जोन प्रभारी गुलाब भंसाली, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष खिलावन साहू संजय कुमार राणा प्यारे लाल मंडावी हरीश कुमार, उषा बढ़ाई ,ताजी राम धनेंद्र, ,पिंटू राणा एवं बूथ के सदस्यगण उपस्थित रहे।

ग्रामीण कांग्रेस सेलुद के तत्वाधान में बूथ कमेटी का बैठक हुआ

अंडा। पाटन विधानसभा के गांव सेलूद में रविवार को ग्राम के ग्रामीण स्तरीय बूथ क्रमांक 4 में बैठक रखा गया।जिसमे सर्वप्रथम बूथ कमेटी में बनाए गए पदाधिकारियों का परिचय दिया गया एवं आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में विधानसभा स्तर पर दिए गए प्रशिक्षण को बूथ स्तर में कार्यकर्ताओं को बताया गया। बैठक में प्रमुख रूप से जवाहर वर्मा, जयश्री वर्मा, खिलेश मारकंडे, संजय यादव, त्रिभुवन यदु, मन्नू यदु, सुभाष बंछोर, सुरेंद्र कुर्रे, भक्तूराम मिरझा, राकेश साहू, भागीरथी, चंद्रकुमार धनकर, रेवाराम धनकर, रामदेव, कौशल यादव, रोहित शिवारे, युवराज, लेखराम धनकर, सुरेंद्र बंछोर, सहदेव, सुखराम यादव, अश्वनी आडिल, लल्लूराम यादव, लीलाधर, करण धनकर, चूरामन यादव आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

जवानों ने मुठभेड़ में नक्सल जनताना सरकार अध्यक्ष को मार गिराया

सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मंगलवार को मुठभेड़ हो गई। इसमें जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया है। उसकी पहचान नक्सलियों के जनताना सरकार अध्यक्ष के रूप में बताई जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन अभी जारी है। एसपी किरण चव्हाण ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। मुठभेड़ एराबोर थाना क्षेत्र में हुई है।

जानकारी के मुताबिक, सीआरपीएफ 219वीं बटालियन और डीआरजी के जवान संयुक्त रूप से मंगलवार सुबह सर्चिंग पर निकले थे। इस दौरान भेज्जी इलाके में नक्सलियों ने अचानक हमला कर दिया। इस पर जवानों ने भी पोजिशन लेते हुए जवाबी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया है। उसे नक्सलियों के जनताना सरकार अध्यक्ष सोढ़ी दुला बताया जा रहा है। फोर्स अभी भी मौके पर है और सर्चिंग जारी है।

3 आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि दी गई

बीजापुर। राज्य शासन की नक्सली पीड़ित व्यक्तियों एवं परिवारों की सुरक्षा एवं पुनर्वास कार्ययोजना के तहत समाज की मुख्यधारा से जोडने के उद्देश्य से कलेक्टर राजेन्द्र कटारा द्वारा जिला पुनर्वास समिति की अनुशंसा पर आत्मसमर्पित नक्सलियों को सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिसके तहत सोमे कुरसम को 2 लाख रुपए, मड़कम बण्डी को 2 लाख रुपए एवं लक्ष्मण हेमला को 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन स्वरूप अनुग्रह राशि प्रदान की गई। गौरतलब है कि शासन से यह राशि नक्सलियों को आत्मसमर्पण के बाद प्रदाय किया जाता है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

जिला पंचायत सदस्य साक्षी राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए

नगरी। झारखंड की राजधानी रांची में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा भारत में स्थानीय लोकतांत्रिक शासन पर तीन दिवसीय (21 - 23 जून) राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें 25 सत्रों में 11 राज्यों से आए करीब 270 सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर- सरकारी संगठनों के सदस्यों, पत्रकारों, सरकारी महकमों के अधिकारियों, अकादमिक जगत से जुड़े लोगों और स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। आयोजन का उद्देश्य भारत में पंचायती राज,पेसा, एफआरए और अन्य सक्षम प्रावधानों के रूप में स्थानीय लोकतंत्र की 30 दशक की यात्रा पर विचार विमर्श करना, पेशेवरों,शिक्षाविदों,नीति विचारकों, जनप्रतिनिधियों और मीडिया के बीच सहयोग को मजबूत करना, अपेक्षाकृत देर से शुरु हुई झारखंड राज्य की स्थानीय लोकतंत्र की यात्रा में योगदान देना,भारत में स्थानीय लोकतंत्र को व्यापक और गहरा बनाने में नागरिक समाज के योगदान को पेश करना रहा। इस संगोष्ठी में सिहावा विधानसभा क्षेत्र के युवा आदिवासी नेता जिला पंचायत सदस्य मनोज साक्षी शामिल हुए।

पीएम आवास की राशि मिलने के बाद भी भवन न बनाने वालों पर होगा मामला दर्ज

कोरबा। नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडेय ने सकरी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना के तहत जिन हितग्राहियों को राशि का आवंटन हो चुका है इसके बाद भी वे उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराएं। उन्होंने अवैध निर्माण के बाद भी नियमितीकरण नहीं कराने वालों पर भी कार्रवाई करने अधिकारियों को हिदायत दी। कार्यपालन अभियंता आरके माहेश्वरी ने बताया कि 31 मई 2022 के पहले जो डीपीआर शासन से मंजूर हुआ था उन सभी आवासों का निर्माण प्रारंभ किया जा चुका है। मुड़ापार में 293 और रामपुर में निर्मित 24 आवासों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर हितग्राहियों को आवास दिया जा चुका है। लाटा के आवासों का आवंटन की प्रक्रिया जारी है। नियमितीकरण के संबंध में बताया गया कि अब तक 1677 प्रकरणों की मंजूरी मिल चुकी है। जिसमें 1ए314 आवासीय और 263 प्रकरण गैर आवासीय है।

धान खरीदी घोटाला मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार

कांकेर। छोटे बेटियां धान खरीदी केंद्र से 37 लाख रुपए की घोटाला करने वाले चार आरोपियों में से 3 आरोपियों खरीदी केंद्र प्रभारी दिलीप बैरागी, बारदाना प्रभारी सुरंजन सरकार, कम्प्यूटर ऑपरेटर विजय राय को छोटे बेटियां पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है, वहीं चौथा आरोपी बांदे लैम्प्स प्रबंधक आरडी. मानिकपुरी है। जिला कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला के आदेश के बाद बांदे जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक ने चार आरोपियों के खिलाफ छोटे बेटियां थाने में धान खरीदी में 37 लाख रुपए की हेरा-फेरी करने का मामला दर्ज कराया था, मामले में छोटे बेटियां धान खरीदी केंद्र प्रभारी दिलीप बैरागी, बारदाना प्रभारी सुरंजन सरकार, कम्प्यूटर ऑपरेटर विजय राय को मंगलवार को गिरफ्तार कर कार्यवाही उपरांत जेल दाखिल कर दिया गया है, वहीं चौथा आरोपी लैम्स प्रबंधक आरडी. मानिकपुरी अभी भी फरार है।

बारिश में समस्याओं का निराकरण करने पहुंचे महापौर

कोरबा। महापौर राजकिशोर प्रसाद को नागरिकों द्वारा शिकायत मिली की कि नालियों के पानी जमाव की वजह से अवरूद्ध होकर दुकानों के सामने आ रहा है, इस पर महापौर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए नगर पालिक निगम कोरबा के अधिकारियों को अवगत कराते हुए सफाई ठेकेदार को पानी के जाम की स्थिति को दूर करने हेतु निर्देशित किया। महापौर श्री प्रसाद ने बताया कि छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल के सख्त निर्देश है कि शहर में बरसात के पानी से जमाव की स्थिति निर्मित न होने पावे। चूंकि कल शाम से ही शहर में हो रही बारिश से जहाँ बड़े-बड़े स्लेब की वजह से कुछ स्थानों पर पानी के जमाव की स्थिति निर्मित हो गई थी, उसके निराकरण हेतु स्वयं महापौर प्रात: गिरते हुए पानी में वार्ड क्र. 13 में पहुंचकर स्थिति का त्वरित निराकरण कराया। इसी प्रकार से शारदा बिहार, चिमनीभट्ठा के लोगों द्वारा फोन पर उन्हें जानकारी दी गई कि नाली का पानी उनके घरों में घूस रहा है। उन बस्तियों में पहुंचकर महापौर ने देखा।

एटक की बैठक में लिए गए अहम निर्णय

कोरबा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद की बैठक मुड़ापार एटक कार्यालय कोरबा में पूर्व जिला सचिव दीपेश मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। जिला सचिव पवन कुमार वर्मा ने बताया कि 6 व 7 जून को राज्य परिषद की बैठक जगदलपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। जिसमें राष्ट्रीय लीडर कृष्णकांत पंडा, डॉ के नारायणन उपस्थित थे। बैठक में कोरबा जिले की जनसमस्याओं को राज्य पार्टी को अवगत कराया गया। जिला परिषद में चर्चा उपरांत कई निर्णय लिए गए। कामरेड राममूर्ति दुबे के केस में पार्टी द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन दिया जाएगा। कोरबा विधानसभा के चारों सीटों पर चुनाव लडने पर चर्चा हुई। पार्टी कोष संग्रह जुलाई में किया जाएगा। कोरबा विधानसभा क्षेत्र में लगातार बैठक कर कमेटी बनाया जाए एवं रामपुर विधानसभा की जिम्मेदारी के आर चौहान और केस राम मन्नेवार को दिया जाए। गेवरा, दीपका, ढेलवाडीह, कुसमुंडा, बलगी क्षेत्र के लिए एक साथ बैठक किया जाए। भाकपा जिला परिषद कोरबा का बैंक खाता खोलने का निर्णय हुआ।

नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू, स्कूलों की छत से टपक रहा पानी

कोरबा। 26 जून को स्कूलों के पट खुल गए। सुबह से हो रही वर्षा ने स्कूलों की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। जिले के 50 प्रतिशत स्कूलों के सिपेज के कारण छत से पानी टपक रहे। साथ ही प्लस्तर उखड़ने के कगार पर हैं। पूर्व तैयारी के अभाव में पहले दिन शाला प्रवेशोत्सव की तैयारी फीकी रही। प्राथमिक शाला मातिन स्कूल में केवल एक विद्यार्थी पहुंचा ।वहीं शहर के गोकुल नगर प्राथमिक शाला में मरम्मत नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को रिसते छत वाले कक्ष में बैठना पड़ा।

नवीन शैक्षणिक सत्र की शुरूआत इस बार दस दिन देर से शुरू हुई है। तेज धूप के कारण शासन ने समय सीमा 16 के बजाए 26 जून कर दिया। 10 दिन अतिरिक्त समय मिलने के बाद भी बच्चों के प्रवेशोत्सव की तैयारी नहीं की गई। जिला शिक्षा विभाग ने इस बार स्पष्ट कर दिया था कि संकुल के अलावा स्कूलों में शाला

प्रवेशोत्सव आयोजित करना है। इसके अलावा स्कूलों में गणवेश व पुस्तकें भी पहुंचा दी गई। तैयारी को लेकर जिला शिक्षा विभाग जानकारी नहीं लिए जाने की वजह से शिक्षकों की मनमानी जारी रही है। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की उपस्थिति भी अधूरी रही है। बच्चों की तरह शिक्षकों ने भी यह मानसिकता बना ली है कि शैक्षणिक सत्र की शुरूआत एक जुलाई से होगी। सरकारी गाइड लाइन के अनुसार शिक्षकों की टीम बना कर बच्चों को शाला प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। शहरी क्षेत्र में अभी तक टीम गठित नहीं की गई है। ऐसे शाला प्रवेशोत्सव में अभिभावकों की सहभागिता फीकी रही है। अव्यवस्था व वर्षा के कारण जहां स्कूलों में शिक्षकों व विद्यार्थियों की उपस्थिति कम रही। बहरहाल स्कूलों में आगामी जुलाई माह तक प्रवेशोत्सव जारी रहेगा। ग्रीष्म काल में स्कूल भवन मरम्मत नहीं कराए जाने की वजह शाला प्रवेशोत्सव की तैयारी पहले दिन औपचारिक ही रही।

शिक्षा के अधिकार के तहत जिले के 296 निजी स्कूलों में 2,346 सीट हैं। इन सीटों के लिए शिक्षा विभाग को कुल 7,225 आवेदन मिले थे। लाटरी सिस्टम से योग्य विद्यार्थियों का चयन किया गया है। चयनित विद्यार्थी 30 जून तक दाखिला ले सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद दाखिला नहीं लिए जाने पर सीट को रिक्त माना जाएगा। द्वितीय चरण के लिए आवेदन एक जुलाई से ली जाएगी। 15 जुलाई अंतिम तिथि होगी। 27 जुलाई से दो अगस्त बीच लाटरी निकाली जाएगी। चयनित विद्यार्थी 14 अगस्त तक प्रवेश ले सकेंगे। जिले के प्राथमिक व माध्यमिक शाला में शिक्षा के अधिकार के अनुरूप सेटअप तय कर रखा है। नियम के अनुरूप प्राथमिक शाला में दो व मिडिल स्कूलों में प्रधान पाठक सहित तीन शिक्षकों का सेटअप है। शिक्षकों की पदोन्नति व सेवानिवृत्ति के कारण अब भी ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक में 312 व मिडिल स्कूलों में 116 शिक्षकों की कमी बरकरार है। एकल शिक्षक की समस्या से जिले को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। शिक्षकों की कमी इस वर्ष भी जारी रहेगी। शिक्षकों को प्रधानपाठक के पद पर पदोन्त एकल शिक्षकीय स्कूल में देना था। नियम विरूद्ध पदोन्ति के कारण एकल शिक्षक स्कूल की समस्या समाप्त नहीं हुई है। आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षक पद के लिए केंद्रीय बोर्ड सीबीएसई से उत्तीर्ण शिक्षकों को ही मान्यता दी जा रही है।

तमाम दावों के बावजूद गांव, कस्बों में जारी है बिजली की अघोषित कटौती

जनकपुर। कभी मेंटेंस के नाम पर तो कभी फॉल्ट के नाम पर बिजली की अघोषित कटौती विकासखंड भरतपुर को विरासत में मिली है। दिन में कभी भी बिजली चली जाती है और फिर आती ही नहीं है। आसरा लगाये लगाये पूरी रात बीत जाती है और सवेरा भी हो जाता है। ऐसी हालत महीनें में एक दो बार नहीं होती है। महीने के 30 दिन में 20 दिन ऐसे ही गुज़र जाते हैं। गर्मी से गर्मी और उमस में जल रहा है भरतपुर विकासखंड के 84 ग्राम पंचायत भयंकर गर्मी में ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी की पूरी रात बिजली गुल रहती है।

बिजली विभाग गांवो की बिजली को फॉल्ट बताकर काट देते हैं लेकिन शहरों और कस्बों को देता है,गरीब जनता ऐसी गर्मी में रात भर चैन की नींद तक नहीं सो पाती हैं। गांवो में लोग बिजली का इंतजार करते रहते की कब बिजली आएगी और हम खाना बनाये। कई बार लोग खाना भी सरसों के तेल का दिया जला कर बनाते हैं। मिट्टी का तेल भी सरकार ने देना बंद कर दिया है। जब बिजली गुल की जाती है तब लोग बिजली विभाग के छोटे कर्मचारियों को कोसते हैं गरियाते हैं। जबकि वो कर्मचारी रात भर बिजली की तारों में फाल्ट ढूढ़ते रह जाते हैं क्योकि कई जगह बिजली के तार जर्जर हालत में हैं तो कई ट्रांसफार्मर भी जर्जर है और उससे भी कई बार बिजली नहीं आती है। सरकार ने बिजली देने का नियम ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटा और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का शासनादेश जारी हुआ था 2021 पर ये नियम तो सिर्फ कागजों में सीमित हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

पटना में विपक्ष की बैठक के बाद रार तेज

नईदिल्ली। अगले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विरोधी गठबंधन बनाने पर सहमत होने के कुछ दिन बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में राज्यस्तरीय राजनीतिक समीकरण को लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगाए। वाम दल शासित केरल एक और राज्य है जहां राजनीतिक समीकरण विपक्षी एकता बनाने के प्रयासों की परीक्षा लेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल इकाई के अध्यक्ष के. सुधाकरन से मुलाकात की और कहा कि कांग्रेस प्रतिशोध की राजनीति से नहीं डरती। केरल कांग्रेस प्रदेश कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष सुधाकरन को पुलिस की अपराध शाखा ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह तो केंद्र में भाजपा के खिलाफ एक बड़ा विपक्षी गठबंधन बनाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन माकपा और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में भाजपा के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करके इसमें बाधा उत्पन्न कर रही हैं।

आवास मरम्मत में गड़बड़ियों की जांच करेगी सीएजी

नईदिल्ली। उपराज्यपाल और आप सरकार के बीच संघर्ष के एक और दौर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम के आवास के पुनर्निर्माण में कथित अनियमितताओं की विशेष ऑडिट करने के लिए सीएजी जांच का आदेश दिया गया है। उपराज्यपाल के कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्रालय ने 24 मई को प्राप्त एक पत्र पर ध्यान देने के बाद विशेष सीएजी ऑडिट की सिफारिश की थी। उन्होंने दावा किया कि पत्र एलजी कार्यालय से प्राप्त हुआ था और इसमें मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के पुनर्निर्माण में घोर और प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया था। केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण पर 44.78 करोड़ रुपये खर्च होने की खबरों के बाद उपराज्यपाल ने पिछले महीने मुख्य सचिव नरेश कुमार को 15 दिनों के भीतर सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित करने और उनकी जांच करने का निर्देश दिया था।

प्रियंका चतुर्वेदी का निर्मला सीतारमण पर कटाक्ष

नई दिल्ली। देशभर में टमाटर की बढ़ती कीमत के बीच मंगलवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तीखा कटाक्ष किया। ट्वीट करते हुए चतुर्वेदी ने पूछा, क्या देश की वित्त मंत्री टमाटर खाती हैं? क्या आप टमाटर की बढ़ती कीमतों का जवाब दे पाएंगे? चतुर्वेदी की टिप्पणी 2019 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्याज की कीमतों पर सीतारमण की टिप्पणी के स्पष्ट संदर्भ में थी। प्याज की बढ़ती कीमतों पर विपक्षी दलों द्वारा रोके जाने पर सीतारमण ने चुटकी लेते हुए कहा कि वह ऐसे परिवार से हैं जिसका सब्जी से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा था, मैं बहुत अधिक प्याज और लहसुन नहीं खाती, इसलिए चिंता न करें। मैं ऐसे परिवार से हूं जिसका प्याज से ज्यादा लेना-देना नहीं है। देशभर के बाजारों में टमाटर की कीमतें 10-20 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 80-100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं।

समाजवादी पार्टी के गढ़ को सुरक्षित करेंगे शिवपाल यादव

लखनऊ। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने स्तर पर चुनावी रणनीति बनाने की शुरुआत कर दी है। सबसे ज्यादा निगाहें उत्तर प्रदेश पर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कवायद तेज हो गई है। पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव को लेकर बड़ी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक के शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। स्थानीय नेता भी उनके नाम पर सहमत हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस पर सहमत हो सकते हैं। हाल में ही अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विधायक पदाधिकारी की एक अहम बैठक बुलाई थी। इसी बैठक के बाद शिवपाल यादव का नाम चर्चा में है।

पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के घोटालों की होगी जांच

हासन (कर्नाटक)। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार पूर्ववर्ती भाजपा शासन के दौरान हुए सभी कथित घोटालों और अनियमितताओं की जांच कराएगी और दोषियों को दंडित करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार उन सभी वादों को पूरा करेगी जो चुनाव के दौरान किए गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पांच गारंटी को लागू करने से सरकारी खजाने पर सालाना 59 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा और इस साल प्रशासन पर थोड़ा अधिक बोझ है। उन्होंने कहा, हम घोटालों की जांच कराएंगे। चार मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया गया और इसमें अनियमितताओं के आरोप हैं, हम इसकी जांच कराएंगे। साथ ही हम 40 फीसदी कमीशन के आरोपों की जांच करवाएंगे। कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य संबंधी खरीद में अनियमितताएं हुईं, सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित अनियमितताएं और बिटकॉइन घोटाला, इन सभी की जांच की जाएगी।

कानून की मार से विपक्ष की जुगलबंदी हो रही है

जिसने देश को लूटा, उसका हिसाब होकर रहेगा: मोदी

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विपक्षी एकता को लेकर जबरदस्त तरीके से तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो दल पटना में जाकर एक दूसरे के साथ खड़े हुए, वे सभी घोटालों की गारंटी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का एक फोटो सेशन का कार्यक्रम हुआ। पूरा विपक्ष 20 लाख करोड़ रुपए की घोटाले की गारंटी है। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि जब कानून इन घोटालेबाजों पर कार्रवाई कर रहा है तो यह एकजुट हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को गारंटी देता हूं कि हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की जाएगी। मेरी गारंटी है कि सभी घोटालेबाजों पर कार्रवाई होगी। हर घोटाले का हिसाब होकर रहेगा।

विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं

मोदी ने कहा कि भाजपा के जो घोर विरोधी दल हैं... 2014 हो या 2019, दोनों ही चुनावों में उतनी छटपटाहट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पहले लोग अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी-पी कर गाली देते थे, आज उनके सामने साष्टांग होते हैं। मोदी ने कहा कि उनकी ये बेचैनी दिखलाती है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है, इसी वजह से तमाम विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं।

गारंटी के बहाने विपक्ष पर वार

प्रधानमंत्री ने कहा कि आजकल बार-बार एक शब्द आता है- गारंटी। ये सारे विपक्षी दल... ये लोग गारंटी हैं भ्रष्टाचार की, ये गारंटी हैं लाखों-करोड़ रुपयों के घोटालों की। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले इनका एक %फोटो ऑप% कार्यक्रम हुआ... उस फोटो में जो लोग हैं उन सब का मिल कर टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिल कर 20 लाख करोड़ रुपये के घोटाले की गारंटी हैं। कांग्रेस का अकेले ही लाखों करोड़ का घोटाला है। राजद, टीएमसी, एनसीपी इन सभी के पास घोटालों की एक लंबी सूची है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों के पास केवल घोटालों का अनुभव है, और उनके पास केवल एक ही गारंटी है जो घोटालों की है। देश को यह तय करना होगा कि वह इस गारंटी को स्वीकार करेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि आज मैं आपको एक गारंटी देना चाहता हूं- अगर उनकी घोटाले की गारंटी है, तो मोदी की भी एक गारंटी है... और यह गारंटी है- हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर-लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी, जिसने गरीब को लूटा है... देश को लूटा है उसका हिसाब तो होकर ही रहेगा। जब जेल की सलाखें सामने दिख रही हैं तो इनकी ये जुगलबंदी हो रही है।

समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री की दो टूक

पीएम मोदी ने मंगलवार को भोपाल में चुनावी राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर तीन तलाक इस्लाम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में तीन तलाक क्यों नहीं है। भोपाल में पांच वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि भाजपा उन लोगों की पार्टी नहीं है जो वातानुकूलित कमरों में बैठते हैं और फरमान जारी करते हैं। भाजपा के लोग जमीनी स्तर पर अथक प्रयास कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी से पहले देश आता है।

पीएम मोदी ने कहा कि समान नागरिक संहिता पर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष की तरफ से समान नागरिक संहिता पर सियासत किया जा रहा है। बीजेपी मुसलमान भाईयों के पास जाकर भ्रम दूर करेगी। पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बूथ स्तर पर टकराव, तू-तू-मैं-मैं की कोई जगह नहीं है। लोगों की सेवा करना बूथ स्तर की राजनीति का मंत्र होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग केवल पार्टी के लिए, पार्टी के फायदे के लिए जीते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कट मनी से उन्हें हिस्सा मिलता है। उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि उन्होंने तुष्टिकरण का रास्ता चुन लिया है। इनकी राजनीति तब तक फलती-फूलती है जब तक गरीब गरीब रहता है। पीएम मोदी ने कहा कि %तुष्टीकरण का रास्ता कुछ समय के लिए काम करता है लेकिन फिर इससे समाज में विभाजन पैदा होता है।

चुनाव सामने हैं इसलिए यूसीसी को बनाया जा रहा मुद्दा : कांग्रेस

भोपाल में तीन तलाक और (समान नागरिक संहिता) यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस के तारिक अनवर ने कहा कि कोई भी कानून बनता है तो वह सबके लिए होता है और उसे उसका पालन करना ही पड़ता है। तो फिर उस बिल पर चर्चा करने की क्या जरूरत है जो पहले ही पारित हो चुका है? उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव सामने हैं और उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया है। डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि समान नागरिक संहिता सबसे पहले हिन्दू धर्म में लायी जानी चाहिए। एससी/एसटी सहित प्रत्येक व्यक्ति को देश के किसी भी मंदिर में पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम यूसीसी नहीं चाहते क्योंकि संविधान ने हर धर्म को सुरक्षा दी है। यूसीसी पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी पर बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गठित विधि आयोग ने विचार कर जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने समान नागरिक संहिता को सही नहीं बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस देश में इसकी आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस नेता और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य आरिफ मसूद ने कहा कि प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए कि उन्होंने डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान की शपथ ली है। देश के सभी वर्गों को संविधान पर भरोसा है और वे इसे बदलने नहीं देंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि यह(समान नागरिक संहिता) एक ऐसा विषय है जिसपर सभी राजनीतिक दलों को, सभी हितधारकों की बात करनी चाहिए...भाजपा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण हो।

कांग्रेस को एक इंच भी जगह देने के मूड में नहीं है तृणमूल कांग्रेस

कोलकाता। पिछले हफ्ते पटना में विपक्ष की बैठक में, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ दूरी पर बैठे देखा गया था। हालांकि, जब ममता बनर्जी बाहर निकल रहीं थीं तब दोनों नेताओं के बीच शब्दों का आदान-प्रदान जरूर हुआ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ अब तक जो योजना बनाई गई है उसमें हर सीट पर मुकाबला वन टू वन रखने पर जोर है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक शिमला में अगली बैठक में चीजें आकार लेंगी।

टीएमसी के अनुसार, बंगाल में जमीनी स्थिति यह है कि विभिन्न स्थानों पर, कांग्रेस, भाजपा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआईएम) ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ हाथ से हाथ मिला रही हैं। टीएमसी और कांग्रेस के बीच दुश्मनी से साफ है कि कोई समझौता नहीं हो सकता। पंचायत चुनाव प्रचार सभा में बनर्जी ने कहा, हम दिल्ली में महाजोत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां कांग्रेस, सीपीआईएम और बीजेपी ने मेरे पीछे महाघोट बना दिया है। मैं उनका महाघोट तोड़ दूंगी। इस टिप्पणी से साबित होता है कि केंद्र में तो गठबंधन हो सकता है, लेकिन बंगाल में टीएमसी कांग्रेस को एक इंच भी जगह नहीं देगी।

इस बीच टीएमसी के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता कुणाल घोष ने बीजेपी-कांग्रेस का एक पोस्टर ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि क्या आप इसे देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? यह बंगाल में आपकी पार्टी की लड़ाई की रणनीति है। वे एनडीए भागीदार के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। टीएमसी बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है और आपकी पार्टी बीजेपी को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही है। पहले आप निर्णय लें कि आपका दुश्मन कौन है? इस तरह की राजनीति ने कांग्रेस को शून्य कर दिया है। दूसरी ओर, कांग्रेस नेता अधीर चौधरी ने टीएमसी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, नीतीश जी ने हमें बुलाया, ममता जी ने राहुल जी से पूछा कि वह कैसे हैं, उन्होंने जवाब दिया बस...ममता वहां जाने के लिए बाध्य हैं, यह मजबूरी है। कांग्रेस हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ती है। कुछ दिन पहले ममता जी ने राहुल जी के बारे में बुरी बातें कहीं थीं। उन्होंने भारत जोड़ो पर कुछ नहीं कहा... । अधीर चौधरी टीएमसी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं। वह टीएमसी को चोर पार्टी तक बता चुके हैं।

केंद्र में सिर्फ छह महीने के लिए है भाजपा सरकार : ममता

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति जबरदस्त तरीके से जारी है। इन सबके बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए अलग-अलग जगहों का दौरा कर रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने जलपाईगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार सिर्फ 6 महीने के लिए है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगले साल फरवरी-मार्च में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। ममता बनर्जी से पहले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि यह पहले भी कराया जा सकता है। ममता ने दावा किया कि अगले लोकसभा चुनाव 2024 में फरवरी-मार्च में होंगे। भाजपा सरकार का कार्यकाल केवल छह महीने का है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सभी बीएसएफ अधिकारियों पर आरोप नहीं लगा रही। वे हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। लेकिन बीएसएफ को निष्पक्षता से काम करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कल भाजपा सत्ता में नहीं रहे, पर उन्हें तो अपना काम करते रहना है।

खेल
प्रमुख समाचार

आईसीसी ने पाकिस्तान बोर्ड को दिया झटका, नहीं बदले जाएंगे मैच स्थल

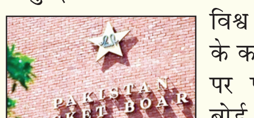

मुंबई। भारत में खेले जाने वाले एकदिवसीय विश्व कप के लिए टीम के कार्यक्रम और स्थलों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने खारिज कर दिया। आईसीसी और बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) द्वारा मंगलवार को जारी विश्व कप के कार्यक्रम में, भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद में निर्धारित है जैसा कि पहले के ड्राफ्ट में प्रस्तावित था। इसमें अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचों के लिए स्थान बदलने के पीसीबी के अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया गया है।

पीसीबी ने आईसीसी और बीसीसीआई से अफगानिस्तान के खिलाफ अपने मैच को चेन्नई से बेंगलुरु और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच को बेंगलुरु से चेन्नई में पुनर्निर्धारित करने के लिए कहा था। पाकिस्तान टीम प्रबंधन को चिंता थी कि चेपॉक (चेन्नई) में पिच स्पिनरों की मददगार होती है और ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ टीम को नुकसान होगा, जिसके पास शानदार स्पिन गेंदबाज हैं। आईसीसी ने हालांकि पाकिस्तान की किसी भी आपत्ति या अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया और यहां तक कि सेमीफाइनल मुकाबला भी मुंबई और कोलकाता में निर्धारित किया है। पीसीबी ने आईसीसी को बताया था कि वह राजनीतिक और राजनयिक कारणों से मुंबई में खेलने में सहज नहीं है। आईसीसी द्वारा पाकिस्तान के अनुरोध पर विचार नहीं करना पहले से अपेक्षित था क्योंकि यह आम तौर पर संभावित सुरक्षा खतरे पर ही आयोजन स्थलों के बदलने पर विचार किया जाता है। पीसीबी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 17 जुलाई तक स्थगित हो गए हैं। ऐसे में यह देखना बाकी है कि बोर्ड विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा पर क्या प्रतिक्रिया देता है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

निफ्टी फिर से 18,800 के रिकॉर्ड स्तर के पार

मुंबई। वैश्विक बाजारों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीन कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया। बाजार जबरदस्त उछाल के साथ हरे निशान पर बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 446 अंकों की उछाल के साथ नए ऑलटाइम हाई पर बंद हुआ। निफ्टी भी 126 अंक चढ़कर 18,817.40 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 446.03 अंक यानी 0.71 फीसदी की बढ़त के साथ 63,416.03 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 63,467.54 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 63,054.84 तक आया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 126.20 अंक यानी 0.68 फीसदी चढ़ा। निफ्टी दिन के अंत में 18,817.40 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी 18,829.25 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 18,714.25 तक आया।

एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लि. का मर्जर

नईदिल्ली। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर अगले महीने की एक तारीख यानी एक जुलाई 2023 से इफेक्टिव हो जाएगा। एचडीएफसी ग्रुप के चेयरमैन दीपक पारिख ने मंगलवार को यह घोषणा की। दीपक पारेख ने बताया कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के बोर्ड मर्जर को मंजूरी देने के लिए 30 जून को बाजार बंद होने के बाद बैठक करेंगे। वहीं, समूह के वाइस-चेयरमैन और सीईओ केकी मिस्त्री ने बताया कि एचडीएफसी स्टॉक डीलिस्टिंग 13 जुलाई से प्रभावी होगी। 13 जुलाई को हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज से हट जायेंगे। बता दें कि इस विलय के लागू होने के साथ एचडीएफसी बैंक दुनिया का 5वां सबसे वैल्यूएबल बैंक बन जाएगा।

26 जून तक एक करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल

नईदिल्ली। आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि 26 जून तक एक करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किये गये हैं और यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक है। वेतनभोगी करदाताओं और ऐसे करदाता, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में हुई आय के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि एक करोड़ आईटीआर दाखिल करने का लक्ष्य पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस साल 12 दिन पहले हासिल कर लिया गया। विभाग ने कहा, इस साल 26 जून तक एक करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं, जबकि पिछले साल आठ जुलाई तक एक करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। विभाग ने करदाताओं से अपना आईटीआर जल्दी दाखिल करने का भी आग्रह किया, ताकि अंतिम समय की भीड़ से बचा जा सके।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट अदाणी ग्रुप के खिलाफ 'लक्षित हमला

नईदिल्ली। अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने अमेरिकी शार्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को झूठा और फर्जी बताते हुए इसे समूह के खिलाफ 'लक्षित हमला' बताया है। अदाणी एंटरप्राइजेज की सालाना रिपोर्ट में गौतम अदाणी ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अदाणी ग्रुप को टारगेट करने के लिए जानकर फैलाई गई 'फर्जी सूचना' थी। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट का मकसद ग्रुप की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना था। एक समय विश्व के टॉप धनी व्यक्तियों की सूची में रहे गौतम अदाणी ने कहा कि हिंडनबर्ग ने भारत के गणतंत्र दिवस से पहले रिपोर्ट जारी की थी। उन्होंने कहा रिपोर्ट ऐसे समय जारी की गई जब कंपनी अपने एफपीओ पेश करने की योजना बना रही थी, जो कि भारत के बाजार इतिहास में सबसे बड़ा एफपीओ हो सकता था।

आईसीसी ने वर्ल्ड कप-2023 के शेड्यूल का किया ऐलान

मुंबई। भारत में इस साल के आखिर में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप का ऐलान आधिकारिक तौर पर कर दिया गया है। 46 दिनों तक चलने वाले इस मेगा टूर्नामेंट का आयोजन भारत में 10 स्थानों पर किया जाएगा। वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर, 2023 से होगी। पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल भी इसी मैदान पर 19 नवंबर को खेला जाएगा। मेजबान भारत अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को चेन्नई में पांच बार के विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा। भारत का मुकाबला पाकिस्तान से 15 अक्टूबर को खेला जाएगा।

राउंड रॉबिन फॉर्मेट में होगा टूर्नामेंट का आयोजन

वर्ल्ड कप में कुल 10 टीमें भाग लेंगी। पहली आठ टीमें पहले ही क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग के माध्यम से क्वालीफाई कर चुकी हैं। अंतिम दो स्थान जिम्बाब्वे में हो रहे क्वालीफायर टूर्नामेंट के अंत में निर्धारित किए जाएंगे, जो 9 जुलाई को समाप्त होगा। प्रत्येक टीम राउंड रॉबिन प्रारूप में अन्य नौ टीमों खेलेगी। इसमें शीर्ष चार टीमें नॉकआउट चरण (सेमीफाइनल) के लिए क्वालीफाई करेंगी।

भारत के मैचों का शेड्यूल

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, 8 अक्टूबर, चेन्नई। भारत बनाम अफगानिस्तान, 11 अक्टूबर, दिल्ली। भारत बनाम पाकिस्तान, 15 अक्टूबर, अहमदाबाद। भारत बनाम बांग्लादेश, 19 अक्टूबर, पुणे। भारत बनाम न्यूजीलैंड, 22 अक्टूबर, धर्मशाला। भारत बनाम इंग्लैंड, 29 अक्टूबर, लखनऊ। भारत बनाम क्वालिफायर, 2 नवंबर, मुंबई। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, 5 नवंबर, कोलकाता। भारत बनाम क्वालिफायर, 11 नवंबर, बेंगलुरु।

टूर्नामेंट के अन्य अहम मुकाबले

टूर्नामेंट के अन्य अहम मुकाबलों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 13 अक्टूबर को लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा। बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मुकाबला रविवार 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसका ऐलान आईसीसी ने कर दिया है। इस मुकाबले में एक लाख से अधिक दर्शकों के होने की उम्मीद है। इससे पहले वर्ष 2019 में खेले गए विश्व कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ी थी, जिनके बीच हुए मुकाबले में भारत ने जीत हासिल की थी। ये मुकाबला मैनचेस्टर में खेला गया था।

इसके अलावा पाकिस्तान 20 अक्टूबर को बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा, जबकि अगले दिन मुंबई में इंग्लैंड का दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला होगा।

भारत 22 अक्टूबर को 2019 के सेमीफाइनल में अपनी हार का बदला लेने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेगा। वहीं, ऑस्ट्रेलिया 4 नवंबर को अहमदाबाद में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड से भिड़ेगा। गत चैंपियन ने चार साल पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। ग्रुप चरण का अंतिम मैच 12 नवंबर को कोलकाता में इंग्लैंड और पाकिस्तान से होगा।

सेमीफाइनल, फाइनल और रिजर्व डे का शेड्यूल

टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल बुधवार 15 नवंबर को मुंबई में और दूसरा सेमीफाइनल अगले दिन कोलकाता में होगा। दोनों सेमीफाइनल में एक अतिरिक्त दिन रिजर्व डे के तौर पर रखा जाएगा। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। फाइनल के लिए 20 नवंबर को भी रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है। सभी तीन नॉक-आउट मैच डे-नाइट होंगे।

भारत को सुपर पावर बनाने मोदी का संकल्प

दीपक कुमार त्यागी

इक्कीसवीं सदी के इस दौर में भारतवासी की आंखों में एक सपना है कि विकसित देश बनकर भारत का दुनिया में परचम लहराए। हालांकि देशवासियों के इस सपने को साकार करने के लिए भारत की पूर्व की सरकारें व मौजूदा सरकार निरंतर प्रयास कर रही हैं। लेकिन जब वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो लगा कि अब %सुपर पावर इंडिया% के मिशन को तेज गति मिलेगी। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश यात्राओं की लंबी फेरहिस्त व उपलब्धियों को देखें तो उनकी हर यात्रा पर सुपर पावर इंडिया के मिशन की स्पष्ट छाप नज़र आती है। उन्होंने विदेशी धरती पर भारत की धाक जमाने का कार्य किया है। भयावह कोविड काल आने के बावजूद भी पूरी दुनिया में पिछले नौ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की धरातल पर कारगर ठोस रणनीति के चलते भारत का डंका आज पूरी दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में बज रहा है। आज विदेशी जमीं पर भी भारतवासी गर्व से अपने आपको हिन्दुस्तानी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राज में आज भारत की छवि का दुनिया में यह आलम है कि कोई भी देश भारत की आज किसी भी क्षेत्र में अनदेखी करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। भारत ने कृषि क्षेत्र, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, तकनीकी, रिसर्च, रक्षा, आईटी, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में कार्य करते हुए जल-थल व नभ से जुड़े क्षेत्रों में अपनी एक विशिष्ट पहचान पूरी दुनिया में बनाने का कार्य किया है, जो सुपर पावर इंडिया मिशन के दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छा संकेत है। दुनिया में भारत की यह स्थिति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राज की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ उनकी कैबिनेट के सहयोगी व दुनिया के किसी भी देश में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग समय-समय पर वैश्विक मंचों पर भारत व भारतवासियों के हक की आवाज़ को बुलंद होकर उठाते हैं। वह दुनिया के विभिन्न मंचों पर तथ्यात्मक बात करते हुए शेर की तरह दहाड़ते हैं और पूरी दुनिया उनको ध्यान से सुनने का कार्य करती है। इस सकारात्मक स्थिति को देखकर हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। देश को सुपर पावर बनाने के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन दिवसीय अमेरिकी यात्रा गये थे, जहां पर उनका भव्य आदर सत्कार हुआ था, मोदी का यह राजकीय दौरे बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई बेहद अहम समझौते हुए हैं। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने व्हाइट हाउस में बैठकर विभिन्न मसलों पर द्विपक्षीय बातचीत कर, आठ बेहद अहम समझौतों पर अपनी रजामंदी की मुहर लगाने का कार्य किया था, जिसमें रक्षा, रेलवे व अंतरिक्ष जैसे बेहद अहम क्षेत्र शामिल हैं। वहीं इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है कि वह राजकीय यात्रा के दौरान दो अवसरों पर अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले पहले भारतीय राजनेता बन गये हैं। वहीं उनके संबोधन के दौरान अमेरिका के सांसदों का बार-बार ताली बजाना उनकी लोकप्रियता व भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाने का कार्य बखूबी करता है।

एनडीए कुनबा बढ़ाने की कोशिशें

समीर चौगांवकर

विपक्षी एकता की सक्रिय कोशिशों के बीच भाजपा ने भी एनडीए का कुनबा दोबारा जोड़ने का प्रयास शुरु कर दिया है। इसी महीने की तीन जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के अपने आवास पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, अकाली दल के नेता नरेश गुजराल और लोकजनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान के साथ एक बैठक की। उस बैठक में उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा एनडीए में शामिल छोटे दलों का सम्मान किया है। 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी हमने हमारे सहयोगी दलों को सरकार में शामिल किया। वह इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहते हैं। दरअसल गृहमंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर अपने पूर्व सहयोगियों से यह इसलिए कहा क्योंकि 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा था कि हमें एनडीए में शामिल सहयोगी दलों को भरोसा दिलाना है कि भाजपा अपने साथियों को पूरा मौका और सम्मान देती है। सहयोगी दल हमारे रास्ते का रोड़ा नहीं, सेतु हैं।

बिहार में नीतीश कुमार के साथ छोड़ जाने और कर्नाटक में बुरी हार के बाद भाजपा नौ माह बाद होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए किसी तरह का जोखिम उठाने को तैयार नही है। इसलिए पुराने सहयोगी दलों को फिर से जोड़कर 2024 में मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। नीतीश कुमार की विपक्ष एकता की मुहिम हो या नए संसद भवन के उद्घाटन पर एक साथ 19 पार्टियों का विरोध या फिर केजरीवाल सरकार के खिलाफ अध्यादेश के विरोध में एक दर्जन पार्टियों का उनके साथ जाना हो, इन सभी घटनाओं ने भाजपा को मजबूर किया है कि वह एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए पहल करे। भाजपा छोटे छोटे दलों को जोड़कर बड़ी जीत के साथ 2024 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना चाहती है। टीडीपी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में भाजपा की पुरानी साथी रही है। लेकिन 2018 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मसले पर चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। भले ही आंध्र प्रदेश में टीडीपी सीटों के हिसाब से विफल रही हो लेकिन उसका वोट प्रतिशत बताता है कि आंध्रप्रदेश में टीडीपी एक ताकत बनी हुई है। टीडीपी के एनडीए में आने से आंध्र प्रदेश में भाजपा को फायदा मिलना तय है। पिछले विधानसभा चुनाव में टीडीपी को 39.26% वोट, और भाजपा को 0.84% वोट मिले थे।

दक्षिण के एकमात्र राज्य कर्नाटक में सत्ता गंवा चुकी भाजपा को लग रहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उसे टीडीपी तथा कर्नाटक में जेडीएस का समर्थन 2024 के लिए अतिरिक्त संजीवनी का काम करेगा। कर्नाटक में कांग्रेस से हारने के बाद भाजपा और जेडीएस को एक साथ आने में भलाई लग रही है। कर्नाटक से आने वाली 28 लोकसभा सीटों में से पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 25 सीटें जीती थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा को 36% वोट और जेडीएस को 13.3% वोट मिले थे, ऐसे में भाजपा और जेडीएस का वोट शेयर मिला दिया जाए तो वह कांग्रेस को मिले वोट से 7 प्रतिशत अधिक हो जाता है। तेलंगाना में इसी साल और आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। भाजपा ने 2024 के आम चुनाव को देखते हुए सहयोगियों की दो श्रेणियां बनाई है। पहली श्रेणी में उन पार्टियों को रखा है जिनके साथ चुनाव के पहले गठबंधन करने की कोशिश कर रही है। दूसरी श्रेणी उन पार्टियों की है, जिनसे संवाद बराबर बना रहे और जरूरत पड़ने पर चुनाव के बाद ये गठबंधन में शामिल हो सकें या भाजपा का समर्थन कर सके। दूसरे श्रेणी की पार्टियों में ओडिशा के नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल जैसे दलों को लिया जा सकता है। 1997 से भाजपा के साथ चुनाव लड़ रही अकाली दल ने कृषि कानूनों के कारण मोदी सरकार से दोस्ती तोड़ ली थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल को बुरी हार का सामना करना पड़ा। अकाली दल को सिर्फ 17 सीटें मिली। पंजाब में आप पार्टी की ऐतिहासिक जीत और जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आप पार्टी की जीत ने अकाली दल और भाजपा को फिर से साथ आने पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है।

बिहार में नीतीश के कारण सत्ता से बाहर हो चुकी भाजपा बिहार में भी एनडीए के पुराने साथियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा से भाजपा का केन्द्रीय नेतृत्व लगातार संपर्क में है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा नीतीश सरकार से अलग हो चुकी है। इसका भी एनडीए में आना तय है। इसके अलावा बिहार में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी फिर से एनडीए में आ सकती है। हालांकि, 2022 के मार्च में उनकी पार्टी के तीनों विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन इस साल फरवरी में सहनी को केंद्र सरकार ने वाइ-प्लस सुरक्षा देकर यह संकेत दिया कि बदली परिस्थितियों में भाजपा उन्हें गठबंधन में लाना चाहती है। दरअसल, सहनी 25 जुलाई को फूलन देवी के शहादत दिवस पर पटना में एक भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हो सकता है उस दिन वह एनडीए में शामिल होने की घोषणा भी कर दें। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त अलग होने वाली लोक जनशक्ति पार्टी के अब दो धड़े बन चुके हैं। पशुपति कुमार पारस का धड़ा अभी एनडीए के साथ है और पारस केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन बिहार भाजपा से केंद्रीय नेताओं को यह जानकारी दी गई है कि एलजेपी से भाजपा को चुनावी लाभ तब ही मिल सकता है जब लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी साथ हों। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर ध्यान दिया और चिराग पासवान को जोड़ने की कोशिश शुरू हो गई। फरवरी में ही केंद्र सरकार ने चिराग को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। भाजपा की कोशिश है कि एलजेपी के दोनों धड़ों में समझौता हो जाए और संयुक्त एलजेपी एनडीए के साथ रहे। इस बात की भी चर्चा है कि मोदी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार में पारस की जगह चिराग को मंत्री बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा मजबूत है फिर भी वह कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और इस कारण भाजपा की सहयोगी रही ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से भी बातचीत चल रही है। दरअसल तमिलनाडु में एआइएडीएमके, महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना और हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को छोड़कर, केंद्र में भाजपा के पास कोई महत्वपूर्ण सहयोगी नहीं है जो राज्य स्तर पर खास फर्क डाल सके। 2024 में इन तीनों की चुनावी क्षमता पर भी सवालिया निशान हैं।

गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के समय एनडीए में 26 पार्टियां थीं। भाजपा 2014 के चुनाव में 282 सीटें जीतीं, जबकि सहयोगियों ने 54 सीटें जीती थीं। शिवसेना ने सबसे ज्यादा 18, तेलगुदेशम पार्टी ने 16, लोजपा ने 6, अकाली दल ने 4, आरएलएसपी ने 3 और अन्य सीटें बाकी छोटे दलों ने जीतीं थी। इनमें से टीडीपी और अकाली दल जैसी पार्टियां अब भाजपा की सहयोगी नहीं हैं। बिहार में नीतीश के साथ भाजपा ने 2019 के चुनाव में 39 सीटें जीती थीं। बिना नीतीश के बिहार में यह प्रदर्शन संभव नहीं है। इस कारण भाजपा को बिहार में छोटे छोटे दलों को साथ लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 2019 में भाजपा ने 303 सीटें जीतीं, वहीं सहयोगियों ने 50 सीटें। इनमें भी जेडीयू और शिवसेना ने अकेले 34 सीटें जीतीं। यानी एक बड़ा हिस्सा इन दोनों पार्टियों ने जीता जो अब भाजपा की सहयोगी नहीं बल्कि विरोधी हैं। राजस्थान में कुछ ही महीनों बाद चुनाव हैं और राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भी एनडीए में लाने की कोशिश हो रही है। बेनीवाल की आरएलपी भी एनडीए का हिस्सा रही है। लेकिन कृषि कानूनों के मुद्दे पर दिसंबर, 2020 में अलग हो गई थी। भाजपा नेताओं को लग रहा है कि अगर बेनीवाल साथ आते हैं तो प्रदेश के जाट मतदाताओं को साथ लाने में मदद मिल सकती है। इसका लाभ राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। विपक्षी एकता की काट के लिए भाजपा को भी सहयोगी दलों की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल, एनडीए का कुनबा कितना बढ़ेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भाजपा इन छोटी पार्टियों के लिए कितना बड़ा मन रखती है और अपने साथ जोड़ने में सफल होती है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

गोपालपूर्वतापिन्युपनिषद् (भाग-8)

गतांक से आगे...

जो (भगवान् श्रीकृष्ण) पाप एवं पापी असुरों के विध्वंशक हैं, (व्रजवासियों की रक्षा हेतु अपने हाथ की एक अँगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, पूतना के प्राणों का अन्त करने वाले और तृणावर्त असुर का संहार करने वाले हैं (उन भगवान् श्रीकृष्ण को नमस्कार है। जो कलाओं से परे हैं, जिनमें मोह का सर्वथा अभाव है, जो स्वरूप से ही परम पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं, अशुद्ध स्वभाव एवं आचरण से युक्त रहने वाले असुरों के शत्रु हैं और जिनसे पृथक् और कोई नहीं हैं, ऐसे महान् भगवान् श्रीकृष्ण को बारम्बार प्रणाम है। हे परम आनन्दस्वरूप परमेश्वर! (आप) मुझ पर प्रसन्न हों, प्रसन्न हों। हे प्रभो! मुझे आधि-व्याधि (मानसिक एवं शारीरिक व्यथा) रूपी सर्पों ने डस लिया है, कृपा करके मेरा उन व्यथाओं से उद्धार करें।

हे श्रीकृष्ण हे रुक्मिणीवल्लभ हे गोपसुन्दरियों के चित्त का हरण करने वाले श्याम सुन्दर मैं इस संसार सागर में डूब रहा हूँ। हे जगद्गुरो! आप मेरा उद्धार करें। हे केशव! हे क्लेशहरण करने में समर्थ नारायण! हे जनार्दन! हे परमानन्दमय गोविन्द! हे माधव! आप कृपा करें, मेरा उद्धार करें। हे श्रेष्ठ मुनियो! जिस प्रकार मैं (ब्रह्मा) इन स्तुतियों के द्वारा परमेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण की उपासना करता हूँ, वैसे ही तुम सभी लोग भी पाँच पदों से युक्त ऊपर कहे हुए अष्टादशाक्षर मन्त्र का जप एवं भगवान् श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुए उनकी उपासना-आराधना में निरन्तर संलग्न रहो। इसके द्वारा संसार सागर से पार हो जाओगे। इस प्रकार से पितामह ब्रह्मा जी ने उन ऋषि-मुनियों को उपदेश प्रदान किया। जो श्रेष्ठ मनुष्य इस पूर्वोक्त पञ्चपद युक्त अष्टादशाक्षर मन्त्र का निरन्तर जप एवं भगवान् श्रीकृष्ण का चिन्तन करता है, निश्चय ही वह भगवान् के उस अनुपम परम अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। वह परमपद गतिशील नहीं, वरन् नित्य एवं स्थिर है; किन्तु फिर भी वह मन से भी अधिक तीव्र गति वाला है।

भगवन्मय होने से ही वह अद्वितीय है। वहाँ तक देवता या वाणी आदि इन्द्रियाँ कभी नहीं पहुँच सकती हैं। इन्द्रियों की जहाँ तक गति है, वहाँ तक वह पूर्व से ही पहुँचा हुआ रहता है। अतः भगवान् श्रीकृष्ण ही परम शाश्वत देव हैं। उन भगवान् का सतत चिन्तन करते रहना चाहिए। मन्त्र जप द्वारा उनके नाम रूप-अमृत का सतत रसास्वादन करना चाहिए और उन्हीं भगवान् का नित्य नियमित भजन करते रहना चाहिए। उन्हीं के भजन में सदैव संलग्न रहे। (परमात्मा) ही सत्य है। इस प्रकार यह उपनिषद् (विद्या) पूर्ण हुई।

क्रमशः..

दानवीर भामाशाह

राजस्थान की धरा अनेक वीर सपूतों की जननी है। यहां आज ही के दिन भामाशाह का जन्म हुआ था। भामाशाह वो नाम है, जो यहां आदर से लिया जाता है। उनके नाम से सरकारी योजनाएं चल रही हैं। और दानवीरों की बात आती है तो भी उनका नाम जुबां पर आ जाता है। वह सैकड़ों बरस पहले महाराणा प्रताप के समय जन्मे थे। कहा जाता है कि, भामाशाह ने प्रताप के लिए अपनी सारी जमा-पूंजी अर्पित कर दी थी।

वो दौर जब मुगलों के हमले हो रहे थे तो भामाशाह ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप को अपना सब-कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने दूजों की भलाई के लिए जीवनभर दान किया। ऐसे दानवीर का जन्म राजस्थान के अलवर जिले में 28 जून, 1547 को हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि, उनके पिता भारमल्ल तथा माता कर्पूरदेवी थीं। भारमल्ल राणा साँगा के समय रणथम्भौर के किलेदार थे। अपने पिता की तरह भामाशाह भी राणा परिवार के लिए समर्पित थे।

महाराणा प्रताप के कष्टों के बारे में जब भामाशाह को पता चला तो उनका दिल दहल उठा। भामाशाह ने मदद की ठानी। उनके पास स्वयं का धन और पुरखों की वसीयत थी। उन्होंने वो सब महाराणा प्रताप को अर्पित कर दिया। इतिहास में ऐसा उल्लेख है कि, राणा के लिए भामाशाह ने 25 लाख रुपए की नकदी तथा 20,000 अशर्फी दीं। तब राणा ने आँखों में आँसू भरकर भामाशाह को गले से लगा लिया। वहीं, राणा की पत्नी महारानी अजवान्दे ने भामाशाह को पत्र के जरिए इस सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त की।

अकबर सोच रहा था कि सेना के अभाव में राणा प्रताप उसके सामने झुक जायेंगे, लेकिन इस धन से तो राणा को नई ताकत मिल गई। चिढ़े हुए अकबर ने क्रोधित होकर भामाशाह को पकड़ लाने को कहा। अकबर को उसके कई साथियों ने समझाया कि एक व्यापारी पर हमला करना उन्हें शोभा नहीं देता। इस पर उसने भामाशाह को कहलवाया कि वह उसके दरबार में मनचाहा पद ले ले और राणा प्रताप को छोड़ दे। मगर, दानवीर भामाशाह ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अकबर से युद्ध की तैयारी भी कर ली। यह समाचार मिलने पर अकबर ने अपना विचार बदल दिया। पुस्तकों में आज भी यह पढ़ाया जाता है कि, भामाशाह से प्राप्त धन के सहयोग से महाराणा प्रताप ने नई सेना बनाई। मुगलों से लोहा लिया और अपने काफी क्षेत्र को मुक्त करा लिया। वहीं, भामाशाह जीवन भर राणा की सेवा में लगे रहे। महाराणा के देहान्त के बाद उन्होंने उनके पुत्र अमरसिंह के राजतिलक में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। इतना ही नहीं, जब उनका अन्त समय निकट आया, तो उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया कि वह अमरसिंह के साथ सदा वैसा ही व्यवहार करे, जैसा उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ किया। ऐसे थे भामाशाह।

वैगनर ग्रुप प्रकरण-आतंक को पालना भारी पड़ता है

नीरज कुमार दुबे

यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की ओर से मोर्चा संभालने वाली निजी सैन्य कंपनी वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन ने बगावत का फैसला वापस लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बड़ी राहत प्रदान की है। हालांकि वैगनर ग्रुप ने अपने आका पुतिन को जिस तरह आंखें दिखाईं उससे दुनिया भर को यह संदेश गया है कि आतंक को पालना और निजी सैन्य समूहों को बढ़ावा देना कितना खतरनाक हो सकता है। भले कोई देश या राष्ट्राध्यक्ष दूसरों के खिलाफ उपयोग करने के लिए आतंक को पाले लेकिन एक दिन वही आतंक या निजी सैन्य समूह उसके लिए भस्मासुर साबित होता है। इसके अलावा, वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद जिस तरह बेलारूस के राष्ट्रपति ने बीच बचाव करवा कर रूस को कुछ मांगों को मानने के लिए मनाया, वह यह भी दर्शाता है कि अपने लगभग ढाई दशक के कार्यकाल में पुतिन पहली बार कमजोर पड़े हैं।

इसके अलावा, जिस तरह रोस्तोव में येवगेनी प्रिगोझिन के साथ सेल्फी लेने और उनसे हाथ मिलाने के लिए रूसियों में होड़ लगी हुई थी उससे यह भी प्रदर्शित होता है कि पुतिन को आंख दिखाने और पुतिन शासन को चुनौती देने की हिम्मत दिखाने वाले को जनता सराह रही है। जनता ने जिस तरह वैगनर ग्रुप के मुखिया को सराहा वह यह भी संकेत देता है कि पुतिन के खिलाफ रूसियों के मन में बगावत की आग भभक रही है। दरअसल रूसी जनता पहले दिन से नहीं चाहती थी कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा जाये। पुतिन ने अपनी सनक में आकर जो युद्ध छेड़ा है उसकी बड़ी कीमत रूसी जनता भी चुका रही है और इस युद्ध के लंबे खिंचते चले जाने से वह आजिज भी आ चुकी है। यही नहीं, रूसी सेना का एक बड़ा धड़ा भी बेहद नाराज बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि यदि राष्ट्रपति पुतिन ने वैगनर ग्रुप की बगावत को लेकर अपने रक्षा मंत्री या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर कोई सख्त कार्रवाई की तो बगावत का झंडा बुलंद किया जा सकता है।

जहां तक वैगनर ग्रुप जैसे निजी सैन्य समूहों को बढ़ावा देने की बात है तो इतिहास गवाह है कि आतंक को प्रश्रय देने वाले खुद उसके सबसे बड़े शिकार बने हैं। जरा याद कीजिये कैसे अमेरिका ने ही एक समय ओसामा बिन लादेन को आगे बढ़ाया और एक समय ऐसा आया कि इस आतंक की चोट 9/11 के रूप में अमेरिका को ही झेलनी पड़ी थी। एक सशक्त उदाहरण अपने पड़ोस पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान ने तमाम आतंकी संगठनों को भारत में आतंक फैलाने के लिए तैयार किया लेकिन आज तहरीक-ए-तालिबान और उसे जैसे तमाम आतंकी संगठन खुद पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। पाकिस्तान ने तालिबान को भी प्रश्रय देकर उसे अफगानिस्तान की सत्ता तक पहुँचाने में मदद की थी लेकिन आज वही तालिबान उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। वैगनर ग्रुप भी एक तरह से पुतिन की ओर से निर्मित किया गया निजी सैन्य समूह है जिसने अब धमकी देकर अपने आका के माथे पर पसीना ला दिया। यही नहीं, चीन अक्सर संयुक्त राष्ट्र में किसी पाकिस्तानी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के प्रयासों में बाधा डालता है तो उसे लगता है कि उसने मुंबई में हुए 26/11 के हमलावरों को बचाकर भारत को झटका दिया है। लेकिन चीन को पाकिस्तान में कार्यरत चीनियों पर बढ़ते आतंकी हमलों को देखकर यह समझ आ जाना चाहिए कि आतंकवाद अपने जन्मदाता या प्रश्रयदाता को भी नहीं बख्शता है।

वैगनर ग्रुप ने भले 2014 में पुतिन की ओर से क्रीमिया पर और 2023 में यूक्रेन के बखमुत पर कब्जा किया लेकिन अब वह सिर्फ भाड़े के टट्टू के रूप में काम करने को राजी नहीं है। येवगेनी प्रिगोझिन अब अपने लिये बड़ी भूमिका चाहते हैं। भले फिलहाल वह बेलारूस के मनाने पर मान गये हों लेकिन उन्होंने जो तेवर दिखाये हैं वह आने वाले समय में भी पुतिन के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं। यदि येवगेनी प्रिगोझिन को पश्चिमी या नाटो देशों का साथ मिल गया तो यह पुतिन के लिए बड़ी मुश्किलों का सबब बन सकता है क्योंकि वैगनर ग्रुप रूस की सैन्य क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखता है।

इस प्रकरण ने यह भी दर्शाया है कि रूस की सैन्य शक्ति को जितना बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता था, हकीकत वैसी नहीं है। यदि खुद को महाशक्ति कहलाने वाला देश युद्ध के समय लड़ने के लिए लड़ाके निजी कंपनी से आउटसोर्स करे तो सवाल उठेगा ही कि परेड के दौरान जिस सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था कहीं वह फैन्सी ड्रेस शो तो नहीं था? वैगनर ग्रुप की बगावत से रूस का जो सच दुनिया के सामने आया है और उससे जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, उसका फायदा उठाने में अमेरिका और नाटो देश कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यह मान कर चलना चाहिए कि वैगनर ग्रुप के टैंक और लड़ाके भले रोस्तोव से बाहर चले गये हों लेकिन असल पिक्चर अभी बाकी है।

रूस-यूक्रेन युद्ध ने यह भी दर्शाया है कि रूस की सैन्य रणनीति पूरी तरह कामयाब नहीं रही है। युद्ध में अब तक जानमाल का सर्वाधिक नुकसान भले यूक्रेन को हुआ हो लेकिन प्रतिष्ठा का नुकसान सर्वाधिक रूस को हुआ है। रूसी सेना के हाथ से कई जीते हुए इलाके निकल गये, रूसी सेना की रणनीतियां विभिन्न मोर्चों पर नाकामयाब रहीं, रूसी सेना के बड़े-बड़े कमांडर युद्ध में मारे गये, युद्ध के बीच में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सैन्य नेतृत्व में बदलाव तक करने पड़ गये, जो रूस दुनिया के कई देशों को हथियार देता है उसे ईरान और चीन से हथियार और ड्रोन तक लेने पड़ गये। यकीनन इस सबसे रूस के महाशक्ति होने के दावे पर गंभीर सवाल उठे हैं। इसके अलावा जिस तरह रूस में सैन्य नेतृत्व के शीर्ष पर बैठे लोगों पर तेजी से परिणाम हासिल करने का दबाव बढ़ रहा है, उसके बारे में इस तरह की खबरें हैं कि यह पुतिन के खिलाफ जल्द ही विद्रोह की शक्ल अख्तियार कर सकता है।

बहरहाल, गलती पर गलती करते चले जाने के चलते पुतिन एकदम अकेले पड़ गये हैं। रूस ने एक छोटा सैन्य अभियान समझ कर जो युद्ध शुरू किया था वह अब अंतहीन होता दिख रहा है। यह संघर्ष जिस तरह दिन पर दिन लंबा और महंगा होता जा रहा है उससे रूस में पुतिन के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ रहा है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद से ही रूस पश्चिमी देशों की ओर से लगाये गये तमाम प्रतिबंधों का सामना कर रहा था। ऐसे में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद रूस के खिलाफ

बापू की दिनचर्या

विश्राम

समाचारपत्रावलोकन से निवृत्त होकर लगभग आधा घंटा बापू झपकी लेते। अखबार देखते-देखते प्रायः उन्हें नींद आ जाती। उस समय कोई बहन- भाई उनको पंखा झलते और उनके तलवों में भी मला जाता माता कस्तूरबा प्रायः समाचारपत्रावलोकन के समय घी मलने का कार्य करतीं। बापू की जब आँखें लग जातीं तब वे अपने कमरे में विश्राम करतीं। अत्यधिक व्यवस्था तथा नींद की पूर्ति न होने से बापू रक्तचाप से आक्रांत हुए। इसी वजह से उन्होंने नींद का कर्ज अदा करने का नियम बना लिया और दोपहर में भोजन के बाद कुछ देर वे जरूर सो लेते। बालक, युवा और वृद्ध-सभी के लिए दोपहर में कुछ देर विश्राम करना वे बहुत आवश्यक मानते। उनकी मान्यता थी कि इस नियम का पालन करके दो गुना काम करने की शक्ति प्राप्त की जा सकती है। द्वितीय गोलमेज परिषद् के समय लंदन में बापू अत्यधिक व्यस्त रहते, उनकी नींद की पूर्ति नहीं हो पाती। इस कारण, जब भाषण होते रहते, वे कुर्सी पर बैठे-बैठे आँखें बंद कर लेते और सोने लगते। इस पर घनश्यामदासजी बिड़ला ने उनसे कहा- यह कुछ अच्छा नहीं लगता कि बड़े-बड़े लोग बैठे हों, भाषण दिए जा रहे हों और आप सोते हों ! बापू बोले- फिर क्या जागरण करके बीमार पड़ना है? और, तुमने कभी देखा भी है क्या कि एक भी महत्त्व के व्याख्यान को मैं न सुन पाया होऊँ? बिड़लाजी का कथन है कि यह बात सही भी थी। यहाँ भी उनका विवेक का मापदंड कुछ अलग था। न मालूम कौन-सी वृत्ति काम करती! जब कभी कोई महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बोलने के लिए खड़ा होता, बापू तुरंत आँखें खोल देते और भाषण की समाप्ति पर फिर नींद ले लेते। एक दूसरा प्रसंग है। पं. मोतीलाल नेहरू के दाह-संस्कार के बाद बापू मोटर से आनंद-भवन (प्रयाग) लौट रहे थे। कई रात तक उन्हें जागरण करना पड़ा था। मोटर में वे सो गए। दुर्योगवश मोटर पेड़ से टकराकर उलट गई। सभी लोग छटककर इधर-उधर जा गिरे। लोग अपनी चिंता छोड़कर बापू को उठाने दौड़े। देखा कि वे घास पर पड़े सो रहे हैं। जगाने पर बोले कि मुझे दुर्घटना का कुछ पता ही नहीं और वे मोटर में आकर फिर निद्रामग्न हो गए। तीसरा प्रसंग दिल्ली का है। प्रसिद्ध विचारक जैनेंद्र कुमारजी बापू से मिलने पहुँचे।

क्रमशः ...

संक्षिप्त समाचार

भाठागांव - रिंग रोड शराब दुकान बंद कराने होगा धरना प्रदर्शन

रायपुर। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के पास भाठागांव रिंग रोड में स्थित शराब दुकान के कारण आसपास क्षेत्र की बस्तियों और कॉलोनियों में रहने वाले नागरिक परेशान हैं । उनकी परेशानी को दूर करने शराब दुकान बंद करने की मांग को लेकर सत्यमेव जयते फाउंडेशन द्वारा क्षेत्रीय नागरिकों के साथ शराब दुकान के पास धरना प्रदर्शन किया जाएगा । सत्यमेव जयते फाउंडेशन के प्रदेश संयोजक कन्हैया अग्रवाल ने का बयान जारी करते हुए बताया कि शराब दुकान बंद करने की मांग को लेकर 13 मई 2023 को कलेक्टर एवं जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन देकर एक गांव में दुकान बंद करने की मांग की गई थी। कलेक्टर ने कहा था उक्त क्षेत्र में होने वाली परेशानी को दूर करने आवश्यक कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग को निर्देशित करेंगे ,जिला आबकारी अधिकारी ने भी कहा था शराब दुकान स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। उल्लेखनीय है कि रिंग रोड में स्थित शराब दुकान के कारण सोनकर पारा, आनंद नगर, ब्रह्मदेव कॉलोनी, वालाफोर्ट सिटी, दंतेश्वरी मंदिर, छर्रीपारा, उत्तम नगर,आस्क सिटी सहित आसपास की महिलाएं नशेडियों के कारण उस मार्ग से गुजरने में से डरती हैं । पूरी सड़क में नशा करने वालों की वजह से वातावरण खराब रहता है ।कॉलोनी और बस्तियों के नागरिक शराब दुकान से होने वाले परेशानी को लेकर उद्वेलित हैं।

राशन कार्डधारियों को सुगमता पूर्वक किया जाए राशन वितरण: भगत

रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अमरजीत भगत ने अपने निवास कार्यालय सरगुजा कुटीर में ,खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में राशन कार्डधारियों को सुगमतापूर्वक राशन वितरण, पिछले वर्ष उर्पाजित धान की कस्टम मिलिंग और आगामी खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीदी के लिए आवश्यक तैयारियों के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री श्री भगत बैठक में प्रदेश में संचालित 13,665 शासकीय उचित मूल्य के दुकानों के माध्यम से राज्य के 74 लाख 76 हजार राशन कार्डधारियों को हर महीने वितरित की जा रही राशन वितरण की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने सभी राशन कार्डधारियों की संवेदनशीलता के साथ सुगमता पूर्वक राशन वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री श्री भगत ने कहा कि अत्यधिक वृद्ध और शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए राशन सामग्री प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए राज्य शासन द्वारा राशन सामग्री के उठाव के लिए उन्हें अपना प्रतिनिधि या नामिनि नियुक्त करने का प्रावधान किया है। प्रदेश में 1.06 लाख ऐसे हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। खाद्य मंत्री श्री भगत ने कहा कि वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के अंतर्गत राज्य के अस्थाई प्रवास करने वाले मजदूर परिवारों को अन्य राज्यों में राशन प्रदाय करने की सुविधा भी राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। माह मई में छत्तीसगढ़ के 515 प्रवासी परिवारों द्वारा अन्य राज्यों में बॉयोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए राशन सामग्री का उठाव किया गया।

राज्य में 22 और पैरामेडिकल संस्थाएं हो रही है बिना मान्यता के संचालित : साहू

रायपुर। अजीत जोगी युवा मोर्चा प्रदेश

अध्यक्ष प्रदीप साहू ने पत्रकारवार्ता के माध्यम से मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रदेश में 7 निजी पैरामेडिकल संस्थाओं को पैरामेडिकल कोर्स के संचालन की अनुमति दी है लेकिन इसके बाद छत्तीसगढ़ में 22 और निजी पैरामेडिकल संस्थाओं का संचालन बिना स्वास्थ्य विभाग के अनुमति के हो रहा है। इसकी जानकारी अजीत जोगी युवा मोर्चा ने सचिव एवं रजिस्ट्रार सह चिकित्सकीय परिषद रायपुर के जितेंद्र तिवारी से की है लेकिन उनका कहना है कि इस पर कार्यावाही का अधिकार कलेक्टर को है। जोगी कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर इस बारे में आवगत कराया है लेकिन अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया है। अजीत जोगी युवा मोर्चा ने इन 22 पैरामेडिकल संस्थाओं से मांग की है कि अगर वे बच्चों की परीक्षा लेने में सक्षम नहीं है तो वे उनकी फीस की दोगुनी राशि वापस करें नहीं तो वे कोर्ट की शरण की शरण में जाएंगे।

जय प्रकाश मौर्य को आयुक्त चिकित्सा का अतिरिक्त प्रभार

रायपुर। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (2010) काडर के अधिकारी जय प्रकाश मौर्य विशेष सचिव(स्वतंत्र प्रभार) खनिज संसाधन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक स्वास्थ्य सेवाओं को चिकित्सा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। जय प्रकाश मौर्य को चिकित्सा आयुक्त बनाये जाने के बाद 2007 के आईएएस अफसर मोहम्मद कैसर अब्दुल हक केवल इस पद के प्रभार से मुक्त होगें शेष प्रभार उनके पास यथावत रहेंगे।

मोदी राज में खेती घाटे का सौदा और किसान बदहाल हो गये : मरकाम

■ छत्तीसगढ़ का किसान देश में सबसे ज्यादा खुशहाल

रायपुर। देश की 78 प्रतिशत आबादी की जीविका का प्रमुख आधार खेती और किसान दोनों बदहाल हो चुके है। मोदी सरकार की नीतियों के कारण देश में खेती घाटे का व्यवसाय बन गयी। डीजल के बढ़े दाम, उर्वरकों की कीमत और कृषि यंत्रों के दाम दुगुने होने के कारण खेती का लागत मूल्य दुगुना हो गया और किसानों का समर्थन मूल्य मोदी राज में मात्र 17 प्रतिशत के औसत से ही बढ़ा है। मोदी राज देश के किसानों के लिये आपदा का काल साबित हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी ने 2014 के चुनाव के पहले वायदा किया था 2022 तक किसानों की आय दुगुनी की जायेगी तथा कृषि उपज के लागत मूल्य का ज्यादा समर्थन मूल्य घोषित किया जायेगा लेकिन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशो को मानने का भरोसा दिलाने वाले मोदी ने हर साल किसानों से धोखा किया। मोदी और भाजपा किसान से दो बड़े वादे कर सत्ता में आए। पहला वादा था, किसान के समर्थन मूल्य की लागत50 प्रतिशत मुनाफा पर निर्धारित करना। दूसरा वादा था कि इस मूल्य निर्धारण के फॉमूले से साल 2022 तक देश के 62 करोड़ किसान की आय दोगुनी हो जाना। दोनों बातें सफेद झूठ साबित हुई है। किसान साल दर साल ठगे जाते रहे।

मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार की अपेक्षा कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ में किसान ज्यादा खुशहाल है। छत्तीसगढ़ के किसानों को उनकी उपज की सबसे ज्यादा कीमत मिलता है। छत्तीसगढ़ में 20 लाख किसानों का कर्जा माफ कांग्रेस सरकार ने किया। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद खेती का रकबा बढ़कर 32 लाख हेक्टेयर हो गया तथा खेती करने वाले किसानों की संख्या 12 लाख से बढ़कर 26 लाख हो गयी। छत्तीसगढ़ में धान का खरीदी भी 55 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 107 लाख मीट्रिक टन हो गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसानों की आत्महत्या का दौर खत्म होकर खुशहाली का दौर शुरू हो गया। रमन राज में 15000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या किया था जो अब छत्तीसगढ़ का किसान आत्महत्या नहीं करता है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के धान उत्पादक किसानों के साथ मोदी सरकार लगातार धोखेबाजी कर रही है। यूपीए सरकार के 10 सालों में धान के समर्थन मूल्य में 142.85 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी थी। जब मनमोहन सरकार बनी तब धान का समर्थन मूल्य 560 रू. था, मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार में धान का समर्थन मूल्य बढ़कर 1360 रू. हो गया था। मोदी सरकार के 10वें साल में धान का मूल्य अब जाकर 2183 रू.घोषित हुआ है जो यूपीए सरकार में मिलने वाली कीमत में मात्र 60.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है।

स्वास्थ्य मंत्री ने 50 बिस्तर क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का किया भूमिपूजन

■ सिंघनपुर रीपा और लोहांडीगुड़ा सीएचसी का किया निरीक्षण

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने जगदलपुर शासकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में 23 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 50 बिस्तर क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का भूमिपूजन किया। उन्होंने 35 लाख रुपए की लागत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बस्तर और 30 लाख रुपए की लागत से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के संभागीय कार्यालय के निर्माण के लिए भी भूमिपूजन किया। बस्तर के सांसद श्री दीपक बैज, चित्रकोट के विधायक श्री राजमन बेंजाम, जगदलपुर नगर निगम की सभापति श्रीमती कविता साहू और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. पैकरा भी इस दौरान मौजूद थे।

स्वास्थ्य मंत्री ने तोकापाल विकासखंड के सिंघनपुर में संचालित ग्रामीण औद्योगिक पार्क की गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने रीपा में कार्यरत महिला समूह के सदस्यों से आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। सिंहदेव ने वहां महिला समूह द्वारा संचालित प्रीमियम बेकरी इकाई द्वारा निर्मित बिस्किट खरीदा। स्वास्थ्य मंत्री ने लोहंडीगुड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण भी किया। उन्होंने वहां मुहैया कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं और दवाईयों की उपलब्धता की जानकारी ली। श्री सिंहदेव ने यहां संचालित ओपीडी का भी जायजा लिया।

पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर मुआवजा मिलने की बात पर भड़के

कोरबा। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री और भाजपा विधायक ननकी राम कंवर कोरबा में उरगा-चांपा नेशनल हाईवे मामले में मुआवजा मिलने की बात को लेकर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि, ऐसा बोलने वाला बेवकूफ और ठेकेदार का दलाल है। कहा कि, अगर कलेक्टर ऐसे लोगों को छोड़ेंगे तो वह भी मार खाएंगे। भाजपा विधायक ने कहा कि, वह इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री से करेंगे। दो दिन पहले ही एनएचएआई के अफसरों ने बताया था कि, विधायक ने छह महीने पहले खुद 2 करोड़ 34 लाख 67 हजार 324 रुपये का मुआवजा लिया, बावजूद इसके अभी तक अपनी राइस मिल नहीं हटाई है।

पूर्व गृहमंत्री ने ननकी राम ने कहा कि, उरगाङ्कचांपा नेशनल हाइवे के लिए जमीन देने वाले दर्जनों ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा दिए बगैर ही उनके मकान को तोड़ दिया गया। अब बारिश में तो बिल्कुल भी तोड़ने नहीं देंगे। वहीं खुद को मुआवजा मिलने के एनएचएआई अफसर के बयान पर कहा कि, मेरे बारे में ऐसा बोलने वाला बेवकूफ है। ये आदमी ठेकेदार का दलाल या गुंडा होगा। उन्होंने कहा कि अगर ठेकेदार का आदमी मेरे सामने आ जाए और बहस करे। मैं बहुत लोगो को मार चुका हूं, नहीं छोड़ूंगा। ननकीराम ने कहा कि, गलत करने वालो को कलेक्टर छोड़ेंगे तो वे भी मार खाएंगे।

चार दिन पहले ही ग्रामीणों के साथ लगाया था जाम

दरअसल, कोरबा-चाम्पा मार्ग पर ग्राम पताढ़ी में हाईवे के लिए ली गई जमीन पर कब्जे को लेकर प्रशासन ने गुरुवार शाम उरगा इलाके में कई मकानों और दुकानों को ढहा दिया। इसके विरोध में शुक्रवार को भाजपा विधायक और पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने ग्रामीणों के साथ मिलकर हाईवे जाम कर दिया। आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना मुआवजा और नोटिस दिए उनके मकानों और दुकानों को गिराया। इसके बाद एनएचएआई के अफसरों ने बताया था कि, विधायक ने खुद मुआवजा लिया है। जब ग्रामीणों ने विधिवत फॉर्म ही नहीं भरा है, तो उनको मुआवजे की रकम भला कैसे जारी होगी।

बिना विधिवत फार्म भरे कैसे मिलेगा मुआवजा

हाईवे अथॉरिटी के अफसरों का कहना था कि, भाजपा के लोग ही कार्य मे व्यवधान उतपन्न कर रहे हैं। पहले वे क्षेत्र की सड़क खराब होने की बात कहते हुए धरना और विरोध जताते रहे। एनएचएआई प्रोजेक्ट के डायरेक्टर डीडी पार्लावार का कहना है कि विधिवत फॉर्म भरकर कई लोगों ने मुआवजा लिया है। जिनका पारिवारिक विवाद है, उनके घर के लोगों ने ही नहीं लिया है, जबकि ऐसे लोगों को कई बार नोटिस दी जा चुकी है। दूसरी तरफ कई ऐसे भी लोग हैं जो मुआवजा लेने के बाद भी निर्माण नहीं हटा रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि जनप्रतिनिधि और जनता निर्माण में सहयोग करें।

एजाज कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भाजपा पार्षद दल पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय

■ लक्ष्मीबाई वार्ड की पार्षद विश्वदिनी पांडेय से की थी 25 लाख की मांग

रायपुर। एक निजी न्यूज पोर्टल के संचालक एजाज कुरैशी के प्रतिनिधि द्वारिका यदु द्वारा अधिवक्ता एवं वर्तमान में वार्ड क्रमांक- 10 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड की पार्षद विश्वदिनी पांडेय से पिछले दिनों 25 लाख रूपये देने एवं पैसा नहीं देने पर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोडूंगा की धमकी दी थी। मंगलवार को भाजपा पार्षद की नेता प्रतिपक्ष मीनल छगन चौबे के नेतृत्व में वरिष्ठ भाजपा पार्षद मृत्युंजल दुबे, प्रमोद साहू के साथ पीडित वार्ड पार्षद विश्वदिनी पांडेय ने रायपुर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर श्रीमती कामिनी कौशल्या देवांगन, श्रीमती गोदावरी गज्जू साहू, श्रीमती सुमन प्रजापति, श्रीमती सरिता आकाश दुबे, श्रीमती सीमा कंदोई के अलावा अन्य पार्षदगण उपस्थित थे।

पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में भाजपा पार्षद ने बताया कि 23 जून 2023 को लगभग 12 बजे द्वारिका यदु नामक व्यक्ति जो कि आदर्श नगर, गली नं.-8, मोवा में रहता है। सामुदायिक भवन में स्थित वार्ड विश्वदिनी पांडेय के कार्यालय में आया और एजाज भाई का मैसेज लेकर आया हूं बोलकर पोर्टल न्यूज मितान भूमि का खबर पढ़कर मजा आ रहा है, अभी तो शुरूआत है आगे-आगे देखना और क्या-क्या होता है और अगर यह सब नहीं चाहती तो एजाज कुरैशी भाईजान की तरफ से जो प्रस्ताव लेकर आया हूं उसको मान लो। भाईजान बोले है कि पार्षद अगर 25 लाख रूपये देगी तो उसके खिलाफ कोई खबर अपने पोर्टल न्यूज में नहीं बनाऊंगा । जिस प्रकार दूसरे लोगों का खबर चलाता हूं वैसा ही उसका भी अच्छा-अच्छा खबर चलाऊंगा और यदि पैसा नहीं देती है तो उसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोडूंगा ।

मैंने द्वारिका यदु से कहा जो करना है कर लो मैं तुम लोगों से डरने वाली नहीं हूं। तब द्वारिका यदु बोला कि एजाज भाई बहुत बड़े पत्रकार है, बड़े-बड़े लोगों के साथ उनका उठना-बैठना और एक साल से तू देख ही रही है उसका कुछ नहीं बिगाड़ पायी, वह कई समाचार तेरे खिलाफ चला चुका है, अब क्या-क्या प्रतीक्षा कर, बहुत जल्दी तूझें दिखेगा, पैसे नहीं देगी तो एजाज भाई चलता है तू तूझे कब मरवा देगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसी धमकी देते हुए द्वारिका यदु मेरे कार्यालय से निकल गया ।

विश्वदिनी पांडेय ने इसके बाद पुलिस महानिदेशक व पुलिस अधीक्षक से एजाज कुरैशी के द्वारा द्वारिका यदु के माध्यम से 25 लाख रुपये की मांग तथा नहीं देने पर बर्बाद व बदनाम करने की धमकी देने के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था। लेकिन इसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मंगलवाल को भाजपा पार्षद दल के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर एक बार फिर से कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

छत्तीसगढ़ की संस्कृति और यहां की माटी की भाजपा को कभी चिंता नहीं रही: सैलजा

रायपुर। राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि 15 साल में भाजपा को छत्तीसगढ़ की संस्कृति और यहां की माटी की कभी चिंता नहीं रही। कांग्रेस सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में एक साथ जारी की जाएगी सभी पदाधिकारीयों की सूची।

भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर विमोचित करने के सवाल पर कुमारी सैलजा ने पत्रकारों को बताया कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और यहां की माटी की भाजपा को कभी चिंता नहीं रही। 15 साल में भाजपा को न छत्तीसगढ़ महतारी की याद आई और न हीं छत्तीसगढ़ के गौरव की। भाजपा को केवल अपनी चिंता रही है। कांग्रेस सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर काम कर रही है। जनता के सामने भाजपा का असली चेहरा उजागर हो चुका है, अपनी बातों को छिपाने के लिए वह वह घर-घर जा रहे हैं, तो कांग्रेस अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही है। लोगों की भावना आज के वक्त में कांग्रेस के साथ है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को 5 साल और देना चाहती है, ताकि जो कार्य अधूरे रह गए हैं वह पूरा कर सके। जनता हमारी मंशा को जानती है। प्रभारी महामंत्री के नियुक्तियों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश सचिव, संयुक्त महासचिव की सूची अभी आना बाकी है। एक साथ सभी पदाधिकारीयों की सूची जारी की जाएगी।

दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बैठक को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा कि दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ बैठक होगी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे, राहुल गांधी समेत सभी नेता शामिल होंगे। इस बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। सेवा भर्ती नियम 2019 के विपरीत शिक्षक भर्ती विज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने और विषय वार विज्ञापन जारी नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया है। भर्ती परीक्षा 10 जून को ही संपन्न कराई गई थी। उसका परिणाम अभी जारी नहीं हुआ है।

याचिकाकर्ता वेदप्रकाश समेत अन्य ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के जरिए हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है। इसमें कहा गया है कि, छत्तीसगढ़ शासन ने शिक्षक के टी-संवर्ग के 4659 पद और ई-संवर्ग के 1113 पदों की भर्ती के लिए 4 मई को विज्ञापन जारी किया था। भर्ती प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्रावधान भी विज्ञापन में बताया गया, जबकि छग स्कूल शिक्षा सेवा संवर्ग भर्ती नियम 2019 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा उक्त पदोन्नति और भर्ती नियम के अनुसार शिक्षक के पद पर विषयवार सीधी भर्ती व पदोन्नति किया जाना है। जो विज्ञापन जारी किया गया वह केवल शिक्षक के लिए है। किसी प्रकार का विषय का वर्गीकरण नहीं किया गया। जबकि सभी विषयों के लिए अलग-अलग पद जारी किया जाना था। ऐसे में अभ्यर्थी को यह भी जानकारी नहीं होगी, कि उसके विषय का पद का रिक्त है या नहीं।

स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने वर्ल्ड बैंक ने मंजूर की 2460 करोड़ की राशि

■ प्रोजेक्ट से 600 मॉडल स्कूलों के विकास एवं संचालन में मिलेगी सहायता

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बेहतर आधारभूत ढांचे के साथ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने छत्तीसगढ़ को लगभग 2460 करोड़ रूपए की राशि मंजूर की है। इस परियोजना से गरीब और कमजोर वर्ग से आने वाले लगभग 40 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने के साथ ही गरीब वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिंदी माध्यम में उत्कृष्ट स्कूल प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचारी पहल भी किए जा रहे हैं। सभी स्तरों में शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर साइंस और कॉमर्स की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ एक्सीलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन (चाक) परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में भी अध्ययन-अध्यापन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में वर्ल्ड बैंक की मदद से राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने, विज्ञान और गणित शिक्षकों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ प्रयोगशालाओं में आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने दूरस्थ स्थानों से पढ़ाई के लिए आने वाले छात्रों के लिए आवास की व्यवस्था, स्कूलों में छात्रों का नामांकन दर बढ़ाने तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया है।

वर्ल्ड बैंक की इस परियोजना से कक्षा 1 से 12वीं तक के लगभग 600 मॉडल स्कूलों को विकसित और संचालित करने में मदद मिलेगी तथा माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और वाणिज्य की शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों, मजबूत नेतृत्व और प्रबंधन सीखने के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। परियोजना से कोविड-19 के दौरान लर्निंग लॉस में कमी आएगी। परियोजना से अध्यापकों के प्रशिक्षण से शिक्षकों की कक्षा में अध्यापन की क्षमता बेहतर होने के साथ ही छात्रों की विषय-वस्तु को सीखने की क्षमता बढ़ेगी। इस परियोजना से छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ते निर्माण और सेवा क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

10वीं-12वीं के मेधावी विप्र छात्र-छात्राएं 29 को होंगी सम्मानित

मैथिल विप्र परिषद छत्तीसगढ़ 10वीं व 12वीं में सफल हुए मेधावी विप्र छात्र-छात्राओं को 29 जून को वृंदावन हॉल सभागार में सम्मानित करने जा रहा है। कार्यक्रम संयोजक नितिन कुमार झा ने बताया कि छत्तीसगढ़ के प्रथम पंचायत मंत्री एव वरिष्ठ विधायक अमितेष शुक्ल मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित रहेंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे करेंगे। विशेष अतिथि के रुप में डॉ. पूर्णप्रकाश झा-प्रांतीय अध्यक्ष मैथिल ब्राह्मण सभा, श्री सुरेश मिश्रा-राष्ट्रीय महामंत्री वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन, श्री सुनील ओझा- प्रबंध संचालक एस.के. केयर हॉस्पिटल, मुख्य वक्ता - डॉ. अशोक त्रिपाठी-वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित रहेंगे।

छत्तीसगढ़ का हर बूथ बहुत मजबूतः साव

घोटालेबाजों की छुट्टी की घंटी बजाने हर बूथ तैयारः डॉ. रमन

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में दिए गए उद्बोधन को छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण की तर्ज पर सामूहिक रूप से सुना। मैक कॉलेज ऑडिटोरियम मे आयोजित लाइव प्रसारण कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत व वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्तागण शामिल हुए। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शंकर नगर मंडल में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव, किशोर महानंद , प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने, मंडल अध्यक्ष अनूप खेलकर, हरीश ठाकुर व वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे।सोनारपाल शक्ति केन्द्र के अंतर्गत ग्राम सोनारपाल के बूथ क्रमांक 260 में प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का सीधा संवाद सुना।

रायपुर के वार्ड क्रमांक 48 के बूथ 56 पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, वरिष्ठ नेता वर्धमान सुराना, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अखिलेश सोनी, पूर्व उपाध्यक्ष खेमराज वैद्य, जिला महामंत्री रमेश ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष मनीषा चंद्राकर, जिला महिला मोर्चा उपाध्यक्ष पुष्पा साहू, युवा मोर्चा जिला महामंत्री राहुल राव, मंडल अध्यक्ष सदर बाजार प्रवीण देवड़ा, वरिष्ठ कार्यकर्ता कृष्ण कुमार अवधिया एवं भाजपा के पदाधिकारीगण तथा अनेक कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। कांकेर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, महावीर सिंह राठौर, दिलीप जयसवाल, देवेंद्र भाऊ, टिकेश्वर जैन, दिपक खटवानी, अरुण कौशिक, गिरधर यादव सहित सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सहित सभी विरोधी दलों के घपले घोटालों, भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा रखते हुए, मनरेगा घोटाले, कोल घोटाले, चारा घोटाले, सारदा घोटाले, टू जी घोटाले सहित सभी बड़े बड़े घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार ही इनकी गारंटी है। हमारी भी एक गारंटी है कि इन घोटालेबाजों को छोड़ेंगे नहीं। भाजपा कार्यकर्ता हर बूथ तक यह बतायें कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है और भाजपा सबके विकास और सबके विश्वास, सबके साथ की गारंटी है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद सुनने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ सशक्तिकरण अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ में इतनी अधिक मेहनत की है कि छत्तीसगढ़ का हर बूथ बहुत मजबूत है। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेरा बूथ सबसे मजबूत के ध्येय के साथ हर बूथ को भाजपा का अभेद्य किला बना दिया है। कांग्रेस के त्रिआयामी घोटालों को हम सब के सामने रखा। अब कांग्रेस की इस अपार भ्रष्टाचार गाथा को हमें हर बूथ तक जनता के बीच जाकर बताना है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा घोटाला हुआ, गोठान घोटाला हुआ, गोबर घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ, आवास घोटाला हुआ, डीएमएफ घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ, कोड्रेन द्वारा दिये गए अतिरिक्त अनाज का घोटाला हुआ, राइस मिलिंग में चावल घोटाला हुआ, अरबों रुपये का कोल घोटाला हुआ, 2 हजार करोड़ का शराब घोटाला हुआ, पीएससी घोटाला हुआ। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार तो घोटालेबाजी की वर्ल्ड चैंपियन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के इतिहास में घोटाला किंग के तौर पर दर्ज होने की पात्रता रखते हैं। भाजपा हर बूथ तक कांग्रेस सरकार के घोटालों की तस्वीर लेकर जायेगी।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री का संवाद कार्यक्रम सुनने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि घोटालेबाजों की छुट्टी की घंटी बजाने हर बूथ तैयार है। भाजपा के कार्यकर्ता अब से कई माह पहले से ही हर एक बूथ को लगातार मजबूत कर रहे हैं। बूथ स्तर पर भाजपा के प्रादेशिक नेताओं के साथ राष्ट्रीय नेताओं तक ने मेहनत की है। यह क्रम लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन दिनों बूथ की तरफ जा रही है लेकिन उसके नेता अपने कार्यकर्ताओं को यह नहीं समझा पा रहे कि घोटालों से आकंठ डूबी भूपेश बघेल सरकार और गुटबाजी के भंवर में फंसी कांग्रेस की कौन सी सूरत लेकर जनता के बीच जाना है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के तमाम घोटालों की दास्तान को भाजपा कार्यकर्ता हर मतदाता तक पहुंचाएंगे।

बारिश से सड़कों की खुली पोल, शहर में जलभराव की स्थिति, आमजन परेशान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले 72 घंटे से हो रही बारिश से शहर की सूरत बदल गई है. पहली बारिश में ही शहर की सड़कें लबालब भर गई हैं. शहर की नालियां उफान पर हैं. घरों और गलियों में जलभराव की स्थिति है. जल विहार कॉलोनी, आनंद नगर, राजा तालाब क्षेत्र, तेलीबांधा चौक, घड़ी चौक, सीएम हाउस के सामने सड़कों पर गड्ढों में पानी भर गया है. इसके अलावा सिविल लाइन, नर्मदा पारा, मौली पारा जैसे इलाको में भी पानी भरा है.

सड़कों में पानी भरे होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. रायपुर के तेलीबांधा तालाब के सामने आनंद नगर में पिछले 3 महीनों से नाला बनाने का काम चल रहा है. जिसके चलते आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय रहवासियों का कहना है कि पिछले 3 महीनों से ये परेशानी हो रही है. काम शुरू होने के समय अधिकारियों और पार्षद ने कहा था कि 8 से 15 दिनों के अंदर नाले का काम हो जाएगा. लेकिन 3 महीना पूरा हो चुका है और अब तक काम पूरा नहीं हुआ है.स्थानीय निवासियों का कहना है कि नाले के गड्ढे की गहराई करीब 10 से 12 फीट है. जिससे दुर्घटना की भी स्थिति बनी रहती है. कई बार विधायक, पार्षद और अधिकारी आए और कहा जल्द काम समाप्त हो जाएगा. लेकिन अब तक काम अधूरा है.

बाबू भैया की कलम से

सावधान; फिल्मों के सहारे छत्तीसगढ़ की साख ना घटे

द केरला स्टोरी फिल्म के निर्माताओं ने फिर कमर कसी है। केरल स्टोरी से देश में एक अलग ही माहौल बनाने का आंशिक सफल प्रयास के बाद छत्तीसगढ़ के चुनाव के ठीक पहले द बस्तर स्टोरी नाम की फिल्म बनाने का निर्णय लिया है। निश्चित ही कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जिसे देखने के बाद भाजपा की विपक्षी पार्टीयों पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बताने का आरोप लगेगा। अपने तरीके व किसी के निजी एजेंडे पर नया नैरेटिव बनाया जायेगा। दोनों पक्षों के लोग फिल्म निर्माण की खबर मिलते ही अपनी अपनी बात कहने लगे हैं। एक का कहना है कि फिल्म रिलीज होने के साथ ही बड़े बड़े नेता टीवी के व अखबारों के माध्यम से इसे देखने की मुफ्त में प्रचार की शैली में अपनी बात रखने लगेंगें। जैसा द कश्मीर फ़ाइल के समय किया गया था।भाजपा के बड़े बड़े नेतागणों ने लोगों को फ़िल्म देखने की प्रेरणा दी। लोगों ने भीषण हिंसा, व न्यूड दृश्य भी बड़े चाव से देखा। अत्याचार व बलात्कार के दृश्य को भी राष्ट्र भक्ति की तरह देखा। कई तरीके होते हैं अपनी बात कहने के, दृश्य दिखाना जरूरी नहीं था। आप अपने गंभीर बयानों व भाषणों के माध्यम से भी अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते थे। पर जब कोई प्रयास ,किसी बात को जनता के मानस पटल पर स्थापित करना का हो तो, यह नया तरीका एक दल ने निकाला है। यह कुछ हद तक सफल भी कहा जा सकता है। इन प्रयासों से हर चुनाव में बहुसंख्यक हिंदुओं को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रयास में पिछले दो लोकसभा चुनाव व विधानसभाओं के चुनाव में हिन्दू वोटों का ध्रुवीकरण साफ दिखाई भी दिया। हिन्दू वोटों की मुट्ठी बंध गई और पांच उंगलियों की तरह विपक्ष बिखर गया। भाजपा समझ चुकी है कि प्रयोग सफल है। लगातार प्रयासों से वह इस मुहिम में लगी है। द कश्मीर फ़ाइल से रामसेतु के रास्ते चल कर यह रस्ता अब तक द केरल स्टोरी तक सफल ही रहा है। इतिहास बदलने की तैयारी करने के पहले जनता के मानस रूपी मैदान में यह प्रेक्टिस मैच शुरु हुआ है। इसी बहाने यह टटोला जा रहा है कि जनता के बीच हमारे नए इतिहास को कितनी स्वीकार्यता है। या तक पूरी स्वीकार्यता हिन्दू समाज में नहीं हो पाई है। लगातार जारी है। थोड़ा आदिपुरुष ने इस प्रयास को झटका जरूर दिया है। विवादित मुंतसिर ने मनोज के चोले में ना सिर्फ इनके प्रयासों को बल्कि हनुमान के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने का गंदा खेल खेल दिया। जैसे ही फ़िल्म आई उसके पहले से ही शायद पूर्व निर्देश के आधार पर भक्तों ने इसका पूर्व प्रचार शुरु कर दिया। कहा प्रभुराम को देखने जरूर जाना है। ऐसी भीड़ उमड़ी कि निर्माता ने करोड़ों जेब के अंदर कर लिए। हींग लगे ना फिटकरी रंग........? डायलॉग से विवाद उठा तो उसे बदल दिया गया,लोगों ने फिर देखा कि आखिर बदला क्या है। निर्माता की पौ- बारह हो गई,मालामाल हो गया। मामला सम्हाल लिया जाता पर इतने में मनोज के भीतर बैठे मुन्तशिर ने कहा हनुमान भगवान ही नहीं वे भक्त है। उनको हमने भगवान बनाया। इतना कहते ही विवाद के सोने में सुहागा चढ गया। अब तो पानी सर से ऊपर चला गया मजबूरी में पूरी ब्रिगेड को विरोध करना पड़ा। आदिपुरुष की सफल राजनैतिक योजना अपना काम नहीं कर पाई,बल्कि खेला बिगाड़ गई। अब द केरल स्टोरी के निर्माताओ ने मुफ्त की पब्लिसिटी मिलने की लालच में छत्तीसगढ़ के चुनाव का माहौल बदलने की रणनीति पर एक फ़िल्म बनाने पर काम तेजी से शुरू कर दिया है। आप एक बात समझिए कि एक फ़िल्म के प्रमोशन में निर्माता को करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाना होता है। मुफ्त में जब काम हो रहा हो,पूरी ब्रिगेड बिना कहे पहले से पूरी तैयार बैठी हो। निर्माता तो पहले ही करोड़ों बचा लेगा। सौदा घाटे का नहीं बेहद फायदे का है। फिल्मवाले की आंख में अर्जुन की तरह मछली तो नहीं दिखती , सिर्फ पैसा ही दिखाई देता है। उसके लिए वो कुछ भी बना सकते हैं। उन्हें स्टोरी में सच है या झूठ उससे कोई मतलब नहीं होता, बस पैसा दो, और पैसा वसूल की गारंटी हो। हुनर तो उनके पास है ही। अब केरल स्टोरी वाले निर्माता की नजर में अपने बराबरी भौगोलिक क्षेत्र वाले प्रदेश छत्तीसगढ़ का एजेंडा फिक्स हुआ है। वे द बस्तर स्टोरी बनाएंगे,प्रश्न है कि वे अगर नक्सल गढ़ के आतंक को दर्शाएंगे तो सबसे ज्यादा हिंसा 15 साल के राज में ही हुई है,क्या दिखाएंगे ? ताड़मेटला, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, भेज्जी(सुकमा), बुर्कापाल,किस्टारम के साथ सबसे बड़ी घटना झीरम कांड में विपक्ष के क्रीमी लेयर के नेता समाप्त हो गए। ये सारी घटनाएं 15 साल के शासन काल में ही घटित हुई। क्या दिखाई जाएगी या उसमें अपना नैरेटिव निर्माता सेट करेगा ,यह देखने की बात होगी। वर्तमान शासन में घटनाएं रुक गई हों यह भी नहीं है बल्कि तुलनात्मक रूप से कम हुई है या कहें थमी है। यह जरूर कहा जा सकता है। अगर आदिवासी बालाओं के साथ पुराने राजशाही के दौरान और अब तक लगातार जो अमानवीय अत्याचार हो रहा है,उसको दिखाने का प्रयास हुआ तो निश्चित रूप से उसमें भी चर्चा 15 साल की भी की जाएगी। क्या नैरेटिव सेट करने निर्माता सुदीप्तो सेन स्टोरी बनाते हैं,यह तो फ़िल्म आने के बाद ही पता चलेगा। यह देखना है कि यह फ़िल्म विधानसभा या लोक सभा चुनाव के पहले रिलीज होती है और क्या प्रभाव डालती है। हमारे अपने आदिवासी क्षेत्र बस्तर को निर्माता द्वारा किस प्रकार दिखाया जाता है। अगर छत्तीसगढ़ की छवि धूमिल करने का प्रयास हुआ तो प्रदेश की जनता अपने प्रदेश की रक्षा के लिए तैयार रहे।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

डरा सहमा तानाशाह लोकतंत्र को धमका रहा हैः मरकाम

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को भाजपा की देश भर में करारी हार और मोदी की विदाई का आभास करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि विपक्षी एकता से मोदी किस कदर भयभीत हैं, यह उनके उस भाषण से साफ हो गया, कार्यकर्ताओं को को सुनाया। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान मोदी के चेहरे से उड़ रही हवाईयों को भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जनता ने भी देखा है। डरे सहमे तानाशाह मोदी सीबीआई, आईटी, ईडी जैसी एजेंसियों के सहारे लोकतंत्र की हत्या कर सत्ता में बने रहना चाहता है। मोदी की बातों से ही यह सच्चाई सामने आ गई है कि वे उपलब्धि नहीं बल्कि तानाशाही की दम पर फिर सत्ता में आने की तैयारी कर रहे हैं। एक हिटलर अपने अनुयायियों को बता रहा है कि लोकतंत्र का गला किस प्रकार से घोंट रहा है और आगे भी वह इससे भी ज्यादा तानाशाही करने की तैयारी कर रहा है। देश की संपत्ति अपने पूंजीपति मित्रों पर लुटाने वाले, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले, देश को महंगाई और बेरोजगारी के हवाले करने वाले, देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर कर्ज में डुबो देने वाले के पास अपने कार्यकर्ताओं को बताने लायक भी एक उपलब्धि नहीं है तो वह जनता को अपनी क्या उपलब्धि बता सकता है? भाजपा भ्रष्टाचार का पर्याय है।

भूपेश सरकार में अनैतिक कार्य करने वाले जाते हैं जेल : धनंजय

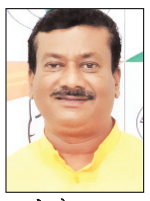

रायपुर । प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में अनैतिक कार्य करने वाले जेल जाते हैं चाहे वह कोई भी हो बिलासपुर में किसान को धमकाने वाला कांग्रेस नेता आज सलाखों के पीछे हैं। 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल के दौरान पूरा प्रदेश ने देखा है कि भाजपा के नेता किसानों की जमीन, सरकारी जमीन, चारागाह, बाग बगीचा और सड़क पर कब्जा कर लेते थे और रमन सरकार उन पर कार्यवाही करने के बजाय उन्हें बचाती थी। पूर्व रमन सरकार में दूसरे नंबर के मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल के परिजनों के ऊपर पद एवं प्रभाव का दुरुपयोग कर सैकड़ों एकड़ शासकीय भूमि को हड़पने और उसे निजी फार्म हाउस बनाने का गंभीर आरोप लगा था। महासमुंद जिला के जलकी गांव में 15.32 हेक्टेयर भूमि अभी राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी जमीन के रूप में दर्ज है इस गंभीर व अरबों रुपए के जमीन घोटाले के आरोपियों के विरुद्ध रमन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की और पीएमओ में भी शिकायत की गई थी जिसमे जमीन घोटाले के आरोपियों को बचाने का काम किया गया है। रमन सरकार के दौरान दंतेवाड़ा में जमीन घोटाला हुआ था, आदिवासियों की जमीन में हेराफेरी की गई थी जिसकी शिकायत आदिवासी वर्ग ने राजभवन तक की है आज भी राजभवन में उस तत्कालीन कलेक्टर और वर्तमान भाजपा नेता ओपी चौधरी के विरुद्ध शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

जल संकट, जल भराव के लिए अधिकारी जिम्मेदारः मीनल

रायपुर। मानसून प्रारंभ होते ही शहर में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है, पहली बारिश में ही पूरा शहर डबरा बन गया है नालों की सफाई के दावे झुठे साबित हो रहें हैं, बहुत ही दुखद: है कि पूरे गर्मी भर शहर की जनता जल संकट से जुझी है और अब पहली बारिश में ही जल भराव की समस्याओं से जुझ रही है। नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जल से संबंधित अधिकारियों को यह भी ज्ञात नहीं है कि शहर के किस वार्ड में जल संकट है और ना ही वो जानना चाहते है। पानी टंकी की सफाई हुई है कि नही, टंकियों की हालत कैसी है इससे अधिकारियों को कोई मतलब नही है। महापौर अधिकारियों से काम लेने में पूरी तरीके से असफल साबित हुए है, क्या कारण है कि करोड़ो रू खर्चे करने के बावजूद जनता को भीषण गर्मी में जल संकट एवं बरसात में जल भराव की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जल भराव की समस्याओं से निपटने के लिए निगम की ओर से कोई सार्थक प्रयास नही किया जा रहा है, भाजपा पार्षद दल ने सभापति को लिखित में आग्रह किया है कि जल्द से जल्द सामान्य सभा आहूत की जावे जिससे समस्त जनप्रतिनिधि जनता की समस्या को सदन मे रख सकें।

जनता का विश्वास खो चुकी भाजपाः शुक्ला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जनता का विश्वास खो चुकी भाजपा अब पंचम विधानसभा के आखिरी सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने का नाटक कर रही है। भूपेश सरकार में विधानसभा के 15 सत्र पूर्ण हो चुके हैं इसमें भाजपा का प्रदर्शन जीरो रहा है और पांचवीं विधानसभा के पावस सत्र में भाजपा के पास मुद्दा नहीं है इसलिए राजनीति करने और मीडिया में बने रहने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का ढोंग कर रही है नाटक और नौटंकी कर रही है। पंचम विधानसभा के 15 सत्र में भाजपा 1 दिन भी पूरे सत्र में व्यवस्थित रूप से बिना हो हंगामा किए बैठ ही नहीं पाई उनका पूरा मकसद सत्र को प्रभावित करना और जनहित के कार्यों पर अड़ंगा लगाना रहा है। भाजपा के विधायक सवाल लगाकर जवाब सुनने से पहले पीठ दिखाकर सत्र से भाग जाते थे और यह दृश्य पूरा छत्तीसगढ़ ने देखा है कि किस प्रकार से भाजपा के विधायक भूपेश सरकार के द्वारा जनहित में लिए जा रहे फैसलों को रोकने के लिए अवरोध उत्पन्न करते थे। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए 36 बिंदुओं के वादों में से 95 प्रतिशत वादों को पूरा किया है। प्रदेश में किसानों को 2660 रु. और 2640 रुपए धान की कीमत मिल रहा है जो देश के किसी भी राज्यों में इतनी कीमत नहीं दिया जा रहा है।

कांग्रेस छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पर स्वांग करती हैः रंजना

रायपुर। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विधायक रंजना साहू ने कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि आश्चर्य की बात है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति का घोर अपमान करने वाली सैलजा छत्तीसगढ़ की चिंता कर रही हैं, संस्कृति की बात कर रही है। कम से कम उनके मुंह से यह शोभा नहीं देता। कांग्रेस के एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का बार बार अपमान हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें बैठक में डांट देते हैं। रायपुर के कांग्रेसी महापौर एजाज ढेबर उनका फोटो गायब करते हैं। सोनिया गांधी के गार्ड उन्हें धक्का दे देते हैं और खुद सैलजा उनके द्वारा जारी नियुक्ति का आदेश निरस्त कर देती हैं। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के 3 राज्य सभा सांसद बाहर के हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विधायक रंजना साहू ने कहा कि भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर विमोचन पर सैलजा को दिक्कत हो रही है। ये क्या छत्तीसगढ़ की बात कर रही हैं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पर स्वांग करती है। असल में वह सोनिया महतारी के चरणों में समर्पित है। छत्तीसगढ़ को लूटकर यहां की जनता का धन दिल्ली भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बहिन बेटियों बुजुर्ग माताओं के साथ दुराचार हो रहा है। कांग्रेस कितना भी दिखावा कर ले, जनता सच जानती है।

गलत तथ्य प्रस्तुत कर कोर्ट को किया गुमराहः राजेश मूणत

रायपुर। पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेश मूणत ने माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चौपाटी बनाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनाये गए फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। मूणत ने कहा कि नगर निगम रायपुर और स्मार्ट सिटी कंपनी ने एजुकेशन हब में चौपाटी का निर्माण संबंध में गलत तथ्य प्रस्तुत करके कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया है। मूणत ने आगे कहा कि हमारा अभी भी मानना है कि रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में नगर निगम चौपाटी बना रहा है,वह अवैध है, हम हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि साइंस कॉलेज ग्राउंड और रविशंकर यूनिवर्सिटी कैंपस एजुकेशन हब है, यहां चौपाटी बनाना अवैधानिक है। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करके नगर निगम रायपुर और स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा पेश किये गए गलत तथ्यों को उजागर करेंगे। न्यायपालिका पर हमारी पूरी निष्ठा है, हमे उम्मीद है कि छात्र हित में चौपाटी के निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाएगी। ननि रायपुर और स्मार्ट सिटी कंपनी ने एजुकेशन हब में चौपाटी का निर्माण संबंध में गलत तथ्य प्रस्तुत किये है,माननीय उच्च न्यायालय ने उसी के आधार पर फैसला सुनाया है। जिस दिन एजुकेशन हब में चौपाटी का विरोध शुरू हुआ था,तब खेल एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नगर निगम रायपुर और स्मार्ट सिटी कंपनी को जमीन ट्रांसफर नहीं की गई थी। नगर निगम रायपुर,स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा कोर्ट में कहा गया है कि चौपाटी का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि जनता के साथ 6 महीने से अवैध चौपाटी के लड़ाई जारी है, इस दौरान भी राज्य सरकार ने अपनी हठधर्मिता को प्रदर्शित करते हुए चौपाटी का निर्माण जारी रखा,जो कि नियम विरूद्ध है। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ के युवा साथियो के लिए बनाये गए एजुकेशन हब में बनाये जा रही अवैध चौपाटी के विरोध में कभी पीछे नहीं हटूंगा और भूपेश बघेल सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जहां तक लड़ाई लड़नी होगी, जरूर लड़ूंगा।

टोल-प्लाजा में कांग्रेसियों ने की तोड़फोड़

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कांग्रेसियों ने टोल-प्लाजा में जमकर तोड़फोड़ की है। असल में टोल पर स्थानीय लोगों से टोल टैक्स लिया जा रहा है। इसी बात का भिलाई शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार शाम को वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ धरना देने पहुंचे थे। इसी दौरान जमकर हंगामा हो गया है।कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के साथ मिलकर टोल पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। इसके अलावा वहां रखे सामानों को भी तोड़ दिया गया है। हंगामे की वजह से करीब 3 घंटे तक रायपुर-नागपुर नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं।

चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टॉफ नर्सेज को डे-केयर कीमोथेरेपी का दिया गया विशेष प्रशिक्षण

रायपुर। कीमोथेरेपी की सुविधा वाले राज्य के 17 जिला अस्पतालों के चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टॉफ नर्सेज को आज डे-केयर कीमोथेरेपी का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। नई दिल्ली के प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. दिनेश पेंढारकर और मध्यप्रदेश राज्य कैंसर कीमोथैरेपी के नोडल अधिकारी डॉ. सी.एम. त्रिपाठी ने इन्हें प्रशिक्षण दिया। राज्य में कैंसर सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में सहयोग के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक श्री भोसकर विलास संदिपन ने डॉ. पेंढारकर और डॉ. त्रिपाठी को प्रशिक्षण कार्यशाला में सम्मानित किया। कार्यशाला में कैंसर केयर मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया गया। एनपी-एनसीडी के उप संचालक डॉ. नेतराम नवरतन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यक्रम प्रबंधक श्री आनंद साहू, शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. प्रदीप टंडन और एनसीडी के राज्य कार्यक्रम समन्वयक डॉ. सुमी जैन भी कार्यशाला में उपस्थित थीं।वर्तमान में प्रदेश के 17 जिला चिकित्सालयों में दीर्घायु वार्ड बनाकर डे-केयर कीमोथेरेपी की सुविधा प्रदान की जा रही है। राज्य के सुदूर जिलों दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, कांकेर, बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा और सूरजपुर सहित बालोद, बेमेतरा, बिलासपुर, गरियाबंद, जांजगीर, कोरबा, मुंगेली, रायपुर तथा धमतरी के जिला अस्पतालों में कैंसर के मरीजों को निःशुल्क कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.